सांध्य दैनिक

नई दृष्टिबिंदु

सच की शक्ति, जनता की दृष्टि

PRGI Reg No - CTHIN/25/A3746

सु-विचार

" चापलूस और आलोचक में बस इतना अंतर है
कि चापलूस अच्छा बनकर बुरा करता है
और आलोचक बुरा बनकर अच्छा करता है...!! "

अज्ञात...

वर्ष–01 अंक–157 | संपादक आलोक तिवारी | दुर्ग, शुक्रवार 26 जून 2026 | पृष्ठ 08 | मूल्य –2 रुपए

मोदी कैबिनेट और भाजपा संगठन में महा–फेरबदल की तैयारी

6 से ज्यादा मंत्रियों की छुट्टी संभव, युवाओं और नए सहयोगियों को मिलेगा मौका

आलोक तिवारी / नईदिल्ली

संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा संगठन में बड़े फेरबदल की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है। कैबिनेट विस्तार के साथ संगठन की नई टीम का खाका भी लगभग तय माना जा रहा है। राजनैतिक विश्लेषकों के मुताबिक यह फेरबदल 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव, परिसीमन बिल और एनडीए के भीतर बदले शक्ति संतुलन को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। कुल 12 से ज्यादा मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं, जबकि 6 या अधिक चेहरों की कैबिनेट से विदाई तय मानी जा रही है।

जॉर्ज कुरियन के इस्तीफे से शुरू हुआ सिलसिला

अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन का राज्यसभा कार्यकाल खत्म होने के बाद इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया। वे सरकार में ईसाई समुदाय के इकलौते प्रतिनिधि थे। उनके जाने के बाद एक व्यक्ति एक पद फॉर्मूले की गाज कई मंत्रियों पर गिर सकती है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष बनाए गए राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा का मंत्रिमंडल से हटना लगभग तय है। वहीं यूपी भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को सामाजिक समीकरण और यूपी चुनाव के मद्देनजर छूट मिलने के संकेत हैं। चुनाव हार चुके रवनीत सिंह बिट्टू नियमों के तहत 6 महीने तक मंत्री बने रह सकते हैं और पंजाब चुनाव लड़ने की चर्चा है।

राज्यसभा कार्यकाल और उम्र बनेगा आधार

यूपी से राज्यसभा सदस्य केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बी एल वर्मा का कार्यकाल नवंबर में खत्म हो रहा है। यूपी में फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए इनके भविष्य पर फैसला अहम होगा। भाजपा 70 पार वाले मंत्रियों की जगह युवाओं को मौका देने के फॉर्मूले पर काम कर रही है। रेल, वित्त, आईटी, कपड़ा, कृषि और जलशक्ति समेत 10–12 मंत्रालयों में राज्य मंत्री स्तर पर बदलाव संभव है। दक्षिण में संगठन मजबूत करने के लिए एक सीनियर कैबिनेट मंत्री को कर्नाटक और दूसरे को मणिपुर भाजपा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। प्रहलाद जोशी का नाम कर्नाटक के लिए चर्चा में है।

शाह–राजनाथ की बैठक में बनी संगठन की रूपरेखा

हाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, बीएल संतोष और आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। माना जा रहा है कि नई संगठन टीम का खाका तैयार है। परंपरा के मुताबिक कुछ कद्दावर संगठन चेहरों को सरकार में जगह मिलेगी, जबकि कुछ मंत्रियों को संगठन भेजा जाएगा। पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा और दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष बदले जा चुके हैं।

राजभवनों में भी दिखेंगे नए चेहरे

कैबिनेट के साथ राजभवनों में भी बदलाव तय है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, मध्य प्रदेश के मंगूभाई पटेल और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का कार्यकाल जुलाई में खत्म हो रहा है। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। कैबिनेट से हटने वाले वरिष्ठ नेताओं को राज्यपाल या राजदूत बनाकर एडजस्ट किया जा सकता है।

पहले सेवा, फिर मेवा : परिसीमन बिल बना कसौटी

फेरबदल में देरी के पीछे भाजपा की रणनीति परिसीमन बिल को बताया जा रहा है। सरकार बिल पास कराने से पहले नए और संभावित सहयोगियों की निष्ठा परखना चाहती है। पिछले 3 महीनों में 33 सांसद एनडीए के पाले में आए हैं। टीएमसी से टूटकर आए 20 सांसदों ने एनसीपीआई नाम से नया गुट बनाकर एनडीए में एंट्री ली है। कोटे के हिसाब से इस गुट को दो मंत्री पद मिल सकते हैं। यह गुट अब एनडीए में भाजपा का सबसे बड़ा सहयोगी बन गया है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना से भी 6 नए सांसद जुड़े हैं। फिलहाल इस गुट से सिर्फ प्रतापराव जाधव मंत्री हैं, इसलिए शिंदे गुट बड़े पदों की मांग कर रहा है। शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले और डीएमके की कनीमोई को लेकर भी अटकलें हैं।

7 राज्यों के चुनाव हैं केंद्र में

यूपी, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, मणिपुर, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर पूरा फेरबदल किया जा रहा है। पिछड़े, अति–पिछड़े और दलित वर्गों की नुमाइंदगी बढ़ाकर चुनावी लाभ लेने की रणनीति है। कुल मिलाकर यह विस्तार पहले सेवा, फिर मेवा के फॉर्मूले पर आधारित है, जहां मंत्री पद से पहले संसद में वफादारी साबित करनी होगी।

पीएम मोदी के बाद अमित शाह ने की राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात, सियासी हलचल बढ़ी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल की चर्चाओं के बीच गुरुवार को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। दो दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रपति से मिले थे। लगातार दो अहम मुलाकातों ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है।

राष्ट्रपति भवन ने साझा की तस्वीर

राष्ट्रपति कार्यालय ने पर बैठक की तस्वीर साझा करते हुए लिखा : "केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की"। इससे पहले 23 जून को पीएम मोदी की राष्ट्रपति से मुलाकात हुई थी। हालांकि दोनों बैठकों का आधिकारिक एजेंडा सामने नहीं आया है।

जॉर्ज कुरियन के इस्तीफे से जुड़ा घटनाक्रम

कैबिनेट फेरबदल की अटकलों को केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन के इस्तीफे से भी बल मिला। केरल से आने वाले कुरियन अल्पसंख्यक मामलों और मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी राज्य मंत्री थे। उनका राज्यसभा कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो गया। भाजपा ने उन्हें दोबारा उच्च सदन में नहीं भेजा। इसके बाद 23 जून को राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया।

क्या कहते हैं जानकार

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावों, क्षेत्रीय संतुलन और संगठनात्मक जरूरतों को देखते हुए मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है। हालांकि सरकार या पार्टी की ओर से फेरबदल की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

क्यों बढ़ी फेरबदल की चर्चा, दो मंत्री बाहर

कुरियन के साथ रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को भी भाजपा ने राज्यसभा के लिए दोबारा नामित नहीं किया। संगठन में जिम्मेदारीहर्ष मल्होत्रा को दिल्ली भाजपा अध्यक्ष और पंकज चौधरी को यूपी भाजपा संगठन में अहम जिम्मेदारी दी गई है। लगातार मुलाकातें पीएम और गृह मंत्री का दो दिन में राष्ट्रपति से मिलना अहम माना जा रहा है।

कौन हैं जॉर्ज कुरियन

65 वर्षीय कुरियन 1980 से भाजपा से जुड़े थे। वे मोदी सरकार में ईसाई समुदाय से इकलौते मंत्री थे। उन्हें अगस्त 2024 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजा गया था। केरल में 17% ईसाई आबादी को देखते हुए उनकी नियुक्ति को अहम माना गया था।

लोन के नाम पर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

कोरबा। जिले में 'सजग कोरबा झ सतर्क कोरबा' अभियान के तहत साइबर थाना पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ठगी की राशि में से 27,070 रुपये नकद बरामद किए हैं। आरोपी यूट्यूब से जानकारी सीखकर लोगों को बैंक लोन का झांसा देकर साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान पुष्पेन्द्र कुमार मेहर (25 वर्ष), निवासी सेमरा थाना डबरा, जिला शक्ति, वर्तमान पता रिस्दी थाना बालको के रूप में हुई है। आरोपी लोगों को आसान किस्तों पर बड़ा लोन दिलाने का झांसा देकर उनके साथ धोखाधड़ी करता था। जांच में सामने आया है कि आरोपी विभिन्न लोगों को अपने प्रभाव में लेकर उनके नाम पर सिम कार्ड जारी करवाता था और उन्हीं सिम का उपयोग साइबर अपराधों में करता था। ठगी के बाद वह सबूत मिटाने के लिए सिम कार्ड नष्ट कर देता था, ताकि उसकी पहचान न हो सके। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने वर्ष 2023 में भी एक व्यक्ति को लोन दिलाने का झांसा देकर 40,000 रुपये की ठगी की थी।

रावघाट में पांच दिन से ठप लौह अयस्क परिवहन, भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन पर उठे सवाल

910 से घटकर 378 रुपये हुआ रेट, वाहन मालिकों का काम बंद, आंदोलन से गर्माया मामला

नई दृष्टिबिंदु / कांकेर

अंतागढ़ विकासखंड की रावघाट लौह अयस्क परियोजना में परिवहन दर विवाद के चलते पिछले पांच दिनों से माल ढुलाई पूरी तरह बंद है। 910 रुपये प्रति टन से शुरू हुआ रेट अब 378 रुपये तक आ गया है। नए ठेकेदार की शर्तों और दरों के विरोध में वाहन मालिकों ने काम रोक दिया है। चर्चा है कि जिन समूहों को बीएसपी ने कभी तवज्जो दी, वही अब प्रबंधन के लिए सिरदर्द बन गए हैं।

340 किमी दूरी कम, फिर भी 910पर होता रहा भुगतान

पहले रावघाट से अंजरैल के रास्ते नारायणपुर, कोंडागांव होते हुए अंतागढ़ रेलवे रैक तक अयस्क जाता था। तब दर 910 रुपये प्रति टन थी। बाद में नारायणपुर से सीधे अंतागढ़ मार्ग शुरू हुआ। पुराने और नए मार्ग में लगभग 340 किमी का अंतर है। आरोप है कि दूरी कम होने के बाद भी पुरानी दर पर भुगतान जारी रहा। यह ठेका देव और नाहर कंपनी के पास मार्च 2026 तक था। ठेका खत्म होने के बाद भी कंपनी को 20 जून 2026 तक काम करने दिया गया और 910 रुपये प्रति टन का भुगतान किया गया।

नए ठेके में दर आधी से भी कम, काम ठप

नया ठेका बिलासपुर की जेके एसोसिएट्स को मिला। कंपनी ने दूरी कम होने का हवाला देकर दर 478 रुपये प्रति टन तय की। स्थानीय वाहन मालिकों को 378 रुपये प्रति टन का प्रस्ताव मिला। वाहन मालिकों का कहना है कि डीजल और रखरखाव की लागत में इस रेट पर काम घाटे का सौदा है। उन्होंने 910 रुपये की दर पर ही भुगतान की मांग करते हुए परिवहन बंद कर दिया।

स्थानीय रोजगार का मुद्दा भी गरमाया

आंदोलन को मजबूती देने के लिए समितियों ने स्थानीय ग्रामीणों को जोड़ते हुए मजदूरों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। कुछ स्थानीय युवाओं का आरोप है कि माइंस में कांकेर जिले की तुलना में नारायणपुर की गाड़ियां और मजदूर ज्यादा हैं, जबकि 90 प्रतिशत अयस्क कांकेर जिले का है। उनका कहना है कि रावघाट के 35 प्रभावित गांवों के ग्रामीणों का शोषण हो रहा है। मामले पर सरकार, प्रशासन और बीएसपी प्रबंधन गंभीर नहीं है। फिलहाल रावघाट से लौह अयस्क की ढुलाई पूरी तरह बंद है और गतिरोध जारी है।

केएलसीसी से वैकल्पिक परिवहन पर भड़का विवाद

बीएसपी ने केएलसीसी के जरिए खदान से छह किमी दूर सरगीपाल तक अयस्क पहुंचाकर रेलवे वैगन से परिवहन शुरू किया। इसकी जानकारी मिलते ही वाहन मालिकों ने 20 जून से जंगल की सड़क पर धरना शुरू कर दिया। कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही। चर्चा है कि विवाद बढ़ाने में पुराने ठेकेदारों की भूमिका है।

बीएसपी में हुए स्क्रैप चोरी के बाद सीआईएसएफ के डीआईजी नागेंद्र नाथ त्रिपाठी का दिल्ली तबादला

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

भिलाई इस्पात संयंत्र में हुए करोड़ो रुपये की स्क्रैप चोरी की घटना के बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भिलाई के डीआईजी आईपीएस नगेन्द्र नाथ त्रिपाठी का तबादला दिल्ली मुख्यालय में कर दिया गया है।

एनएन त्रिपाठी 2009 बैंच के पश्चिम बंगाल कैडर के आईपीएस अधिकारी है तथा वर्तमान समय में सीआईएसएफ में प्रतिनियुक्ति के पर डीआईजी के पद पर अपनी सेवा दे रहे हैं। नागेंद्र नाथ त्रिपाठी के स्थान पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बोकारो के पूर्व पुलिस अधीक्षक भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी चंदन कुमार झा की सीआईएसएफ भिलाई के डीआईजी के पद पर पदस्थापना की गई है लेकिन सूत्रों का कहना है की हाल ही में झारखंड कैडर से सीआईएसएफ में प्रतिनियुक्ति पर गए बोकारो के पूर्व एसपी चंदन कुमार झा को इस इकाई की कमान बतौर डीआईजी पद पर मिल सकती है।

वहीं, भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत उप कमांडेंट निधि सिंह को भी यहां से स्थानांतरित करते हुए केओपीए कोलकाता इकाई भेजा गया है। जबकि सेल के इस्को बनर्पुर इस्पात संयंत्र यूनिट के डीआईजी एल.के. हाकिप का तबादला कोलकाता एयरपोर्ट कर दिया गया है। उनकी जगह नागपुर एयरपोर्ट में सीनियर कमांडेंट के पद पर कार्यरत दिलीप कुमार को डीआइजी बनाते हुए इस्को बनर्पुर इस्पात संयंत्र के सुरक्षा की नई जिम्मेवारी सौंपी गई है।

डोंगरगढ़ में परिक्रमा पथ निर्माण के विरोध में कांग्रेस का अल्टीमेटम, 30 जून को चक्का जाम की दी गई चेतावनी

नई दृष्टिबिंदु / डोंगरगढ़

डोंगरगढ़ में प्रस्तावित परिक्रमा पथ के निर्माण को लेकर सियासत गरमा गई है। जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव के महामंत्री विजयराज सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर परिक्रमा पथ का निर्माण तत्काल निरस्त करने की मांग की है। साथ ही बाईपास निर्माण शीघ्र शुरू करने और शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए प्रशासन को एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है।

पत्र में क्या आरोप लगाए गए?

विजयराज सिंह ने पत्र में कहा कि परिक्रमा पथ की शहर को कोई आवश्यकता नहीं है। सभी धार्मिक स्थल पहले से ही मुख्य मार्गों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मार्ग का अप्रत्यक्ष उद्देश्य रसूखदार लोगों की जमीन को लाभ पहुंचाना और ज्यादा मुआवजा दिलाना है। पत्र में लिखा गया कि परिक्रमा पथ से शहर को कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि कृषि भूमि की हानि होगी और मकान तोड़ने से जनता को आर्थिक नुकसान होगा।

बाईपास और यातायात पर सवाल

पत्र में कहा गया कि डोंगरगढ़ को वर्षों से बाईपास की जरूरत है, लेकिन हर बार यह कागजों में ही रह जाता है। पिछले 2–3 साल में यातायात दबाव बढ़ने से लगभग 10 मौतें और सैकड़ों दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। आरोप है कि बजट में बाईपास शामिल नहीं किया गया, इसलिए काम शुरू होने से पहले ही निरस्त हो गया।

कांग्रेस ने सुबह 6 से रात 11 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक, इंडेन गैस एजेंसी, हाई स्कूल चौक और थाना चौक पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की मांग भी दोहराई। पत्र में दावा किया गया कि पहले तैनात किए गए आरक्षकों को कुछ महीनों में ही हटा दिया गया।

30 जून को चक्का जाम की चेतावनी

विजयराज सिंह ने प्रशासन को एक सप्ताह का समय देते हुए चार मुख्य मांगें रखी हैं: परिक्रमा पथ निर्माण निरस्त किया जाए। बाईपास निर्माण कार्य शीघ्र शुरू हो। सुबह 6 से रात 11 बजे तक भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगे और शहर के तीन मुख्य स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस तैनात हो। पत्र में चेतावनी दी गई कि यदि एक सप्ताह में मांगें पूरी नहीं हुई तो 30 जून, मंगलवार को कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन कर मुख्य मार्ग पर चक्का जाम करेगी। विजयराज सिंह ने कहा कि आंदोलन मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

किसे भेजी गई प्रतिलिपि : यह पत्र लोक निर्माण मंत्री, राजनांदगांव के प्रभारी मंत्री, गृह मंत्री और जिलाधीश राजनांदगांव को भी भेजा गया है। पत्र पर विजयराज सिंह के साथ समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता और आम नागरिक गण, डोंगरगढ़ ब्लॉक के हस्ताक्षर हैं। प्रशासन की ओर से इस पत्र पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

रायपुर–गेवरा लोकल सहित 10 ट्रेन रद्द

रायपुर। रायपुर से बिलासपुर के बीच रोजाना मेमू और पैसेंजर ट्रेनों से सफर करने वाले दैनिक यात्रियों को 26 जून से 29 जून तक भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास के तहत रायपुर रेल मंडल के निपनिया–भाटापारा सेक्शन के बीच रोड अंडरब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है। रिलिविंग गडर्रो के डी–लॉन्चिंग कार्य के लिए रेलवे ने ट्रैफिक–सह–पावर ब्लॉक लिया है। इस वजह से रायपुर–बिलासपुर, रायपुर–कोरबा और इतवारी पैसेंजर समेत 10 महत्वपूर्ण लोकल ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि 3 ट्रेनों को बीच में ही समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इसलिए यात्रियों को यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरुर जांच लेने की सलाह दी गई है। **रद्द होने** वाली गाड़ियां 68746 रायपुर–गेवरा रोड़ मेनू पैसेंजर 25 एवं 28 जून को रद्द रहेगी। 58205 रायपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) पैसेंजर 25 एवं 28 जून, को रद्द रहेगी। 68745 गेवरा रोड–रायपुर मेमू पैसेंजर 26 एवं 29 जून 2026 को रद्द रहेगी। 58206 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) रायपुर पैसेंजर 26 एएवं 29 जून. को रद्द रहेगी। 58202 रायपुर –बिलासपुर मेमू पैसेंजर 26 एवं 29 जून को रद्द रहेगी।

नशे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर, 5 जजों ने छात्रों को किया जागरूक

महावीर जैन स्कूल में एनडीपीएस कानून, साइबर क्राइम और ट्रैफिक नियमों की दी जानकारी

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग ने श्री महावीर जैन पब्लिक स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर लगाया। शिविर में जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग के पांच न्यायाधीश शामिल हुए और छात्रों को कानून व नागरिक कर्तव्यों की जानकारी दी।

5 न्यायाधीश रहे मौजूद

कार्यक्रम में न्यायाधीश श्रीमती श्वेता पटेल, रवि कुमार कश्यप, श्रीमती अंजली सिंह, श्रीमती महिमा शर्मा और सुश्री आरती ध्रुव विशेष रूप से उपस्थित रहे। विद्यालय की प्राचार्य सुनाली पातरा सहित समस्त स्टाफ ने न्यायाधीशों का स्वागत किया।

एनडीपीएस एक्ट पर विस्तार से चर्चा

न्यायाधीशों ने छात्रों को एनडीपीएस अधिनियम के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि नशा सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि परिवार, पढ़ाई और भविष्य को भी बर्बाद करता है। छात्रों को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

साइबर क्राइम और ट्रैफिक नियम भी समझाए

छात्रों को बिना हेलमेट और बिना लाइसेंस वाहन न चलाने की समझाइश दी गई। साथ ही मोबाइल व इंटरनेट से होने वाले साइबर अपराधों, ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, संदिग्ध लिंक और ओटीपी शेयर करने के खतरों की जानकारी दी गई। साइबर फ्रॉड से बचाव के उपाय भी बताए गए।

छात्रों ने पूछे सवाल

शिविर में छात्रों ने उत्साह से हिस्सा लिया। उन्होंने कानून, न्याय व्यवस्था और साइबर सुरक्षा पर कई सवाल पूछे। न्यायाधीशों ने सरल भाषा में सभी सवालों के जवाब दिए और उनकी जिज्ञासा शांत की।

नशामुक्त जीवन का संदेश

कार्यक्रम के अंत में छात्रों को नशामुक्त जीवन, सुरक्षित डिजिटल व्यवहार और कानून के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश दिया गया। यह शिविर छात्रों में कानूनी समझ और सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ाने में उपयोगी रहा।

10 ग्राम पंचायतों में ओपन जिम निर्माण के लिए मिली प्रशासकीय स्वीकृति

दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में 10 विकास कार्यों के लिए कुल 60 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा द्वारा अनुशंसित उक्त कार्यों का संपादन क्रियान्वयन एजेंसी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत धमधा द्वारा किया जाएगा। जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अहिवारा विधानसभा के धमधा विकासखंड के अंतर्गत कुल 10 ग्राम पंचायतों में ओपन जीम निर्माण कार्य की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत ग्राम पंचायत मलपुरीखुर्द, ग्राम हिंगनाडीह (ग्राम पंचायत ढौर), ग्राम पंचायत खपरी (गि), ग्राम करहीडीह (ग्राम पंचायत डूमर), ग्राम पंचायत लहंगा (ढौर), ग्राम पंचायत ढौर (खेरधी), ग्राम पंचायत सहगांव (पथरिया), ग्राम पंचायत नंदौरी, ग्राम पंचायत चेटुवा तथा ग्राम पंचायत ढाबा में प्रत्येक ओपन जिम निर्माण कार्य हेतु 06-06 लाख रूपए (कुल 60 लाख रूपए) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

खास खबर

पारिवारिक विवाद में पिता की हत्या का खुलासा, आरोपी पुत्र को पुलिस ने किया गिरफ्तार

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

थाना बोरी क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के चलते हुई एक व्यक्ति की मौत के मामले में पुलिस ने जांच के बाद हत्या का खुलासा करते हुए मृतक के पुत्र को ही आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक सूचना देने वाला युवक ही जांच में हत्या का आरोपी निकला। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 जून 2026 को ग्राम नवागांव वार्ड क्रमांक 06 निवासी नीलकमल साहू ने थाना बोरी पहुंचकर सूचना दी थी कि उसके पिता कुलेश्वर साहू घर में मृत अवस्था में पड़े हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई।

जांच के दौरान घटनास्थल निरीक्षण, पंचनामा, गवाहों के बयान एवं अन्य साक्ष्य एकत्र किए गए। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें चिकित्सकों ने सिर पर गंभीर चोट लगने को मृत्यु का कारण बताया तथा मृत्यु की प्रकृति हत्या होना प्रमाणित किया। मर्ग जांच एवं पूछताछ के दौरान यह तथ्य सामने आया कि मृतक कुलेश्वर साहू और उनके पुत्र नीलकमल साहू के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था। विवाद के दौरान आरोपी पुत्र द्वारा अपने पिता के साथ मारपीट की गई, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनकी मृत्यु हो गई।

जांच में पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने प्रार्थी नीलकमल साहू को ही आरोपी बनाते हुए उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) एवं 238 के तहत अपराध दर्ज कर विधिवत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार घटना का कारण पारिवारिक विवाद बताया गया है। प्रकरण में संबंधित साक्ष्य सामग्री भी जब्त की गई है। इस कार्रवाई में थाना बोरी प्रभारी, विवेचना अधिकारी, प्रधान आरक्षक एवं थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि पारिवारिक विवादों का समाधान शांतिपूर्ण और वैधानिक तरीकों से करें तथा किसी भी संदिग्ध या आपराधिक घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

चंदखुरी केनाल पारा में बदहाल सड़क बनी हादसों की वजह, लोग हो रहे परेशान

दुर्ग। दुर्ग -बालोद को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर ग्राम चंदखुरी के केनाल पारा में पीएचई विभाग की लापरवाही से सड़क दुर्घटना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। विभाग द्वारा डामरीकरण सड़क को खोदने के बाद केवल मिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है, जिससे बारिश के दिनों में सड़क की हालत बेहद खराब हो गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण सड़क पर कीचड़ और गड्ढे बन गए हैं, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिन में किसी तरह लोग संभलकर निकल जाते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में यह जगह दिखाई नहीं देने से दुर्घटना की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग से रोजाना सैकड़ों लोग आवागमन करते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे, मजदूर, किसान और अन्य वाहन चालक इसी रास्ते पर निर्भर हैं, लेकिन सड़क की यह बदहाली उनकी परेशानी का कारण बन चुकी है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पीएचई विभाग ने कार्य तो शुरू किया, लेकिन उसे अधूरा छोड़ दिया। सड़क की मरम्मत नहीं होने से आम जनता को जोखिम उठाकर गुजरना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन भी इस समस्या को लेकर अब तक गंभीर नजर नहीं आ रहा है। ग्रामीणों और राहगीरों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत कराई जाए और इस लापरवाही पर जिम्मेदार विभाग के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके।

विद्यालयों में प्रार्थना व सांस्कृतिक गतिविधियां जारी रखने के निर्णय का गायत्री परिवार ने किया स्वागत

विद्यालयों में प्रार्थना व सांस्कृतिक गतिविधियां जारी रखने के निर्णय का गायत्री

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

गायत्री परिवार दुर्ग ने प्रदेश के स्कूलों में प्रार्थना, गायत्री मंत्र एवं नैतिक-सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन को निरंतर जारी रखने के राज्य सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए प्रदेश के शिक्षा मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। इस संबंध में संगठन के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में कहा गया कि विद्यालयों में प्रार्थना, प्रेरणादायी मंत्र, राष्ट्रभावना एवं सांस्कृतिक गतिविधियां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में अनुशासन, नैतिकता, आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और सामाजिक समरसता जैसे मूल्यों का विकास होता है।

गायत्री परिवार ने अपने ज्ञापन में उल्लेख किया कि शिक्षा का उद्देश्य केवल शैक्षणिक ज्ञान तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों में मानवीय गुणों और श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण भी समान रूप से आवश्यक है। ऐसे में विद्यालयों में नैतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन व्यक्तित्व विकास की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। पदाधिकारियों ने शिक्षा विभाग एवं शिक्षा मंत्री के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि इस निर्णय से विद्यार्थियों में संस्कार आधारित शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही उन्होंने मांग की कि विद्यालयों में इन गतिविधियों का संचालन आगे भी निरंतर जारी रखा जाए।

विकास कार्यों की सौगात, तीन वार्डों में महापौर ने किया भूमिपूजन

नगर पालिक निगम दुर्ग क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देते हुए महापौर अलका बाघमार ने आज वार्ड क्रमांक .02 राजीव नगर में आर.सी.सी. नाली व पुलिया निर्माण कार्य एवं देवेंद्र कसेर से आजाद दुर्गा चौक तक आरसी सी नाली निर्माण कार्य के अलावा वार्ड क्र.21 आशा नगर बंद गली में सी.सी. रोड निर्माण, सड़क नंबर 14 आशा नगर व सिंधिया नगर में नाली, पुलिया एवं वार्ड क्रमांक 51 दुर्गा चौक प्रगति नगर में सड़क, नाली एवं पुलिया निर्माण कार्यों का विधिवत भूमिपूजन किया। इस दौरान लोक कर्म प्रभारी देवनारायण चन्द्राकर, एमआईसी सदस्य शिव नायक, पार्षद विद्यावती सिंह, पार्षद साजन जोसफ, गोविंद्र देवांगन, रंजीता पाटिल, सावित्री दमाहे, जिला भाजपा प्रवक्ता अरुण सिंह, मनमोहन शर्मा सहित बड़ी संख्या में वार्डवासी उपस्थित रहे।

बता दे कि वार्ड क.02 राजीव नगर में आर.सी.सी. नाली व पुलिया निर्माण कार्य लागत 15,25 के अलावा देवेंद्र कसेर से आजाद दुर्गा चौक तक आरसीसी नाली निर्माण कार्य लागत 10 लाख और वार्ड क्रमांक 21 नाली/पुलिया 9.92 एवं आशा नगर बन्द गली में सीसी रोड निर्माण 9.92 से होगा निर्माण कार्य के अलावा वार्ड क्र.51 मधुबन नगर ठाकुर के घर से एक्का के घर तक गली नं.01 से 03 तक सीमेंट सड़क निर्माण कार्य लागत राशि रु. 8.00 लाख, बोरसी उत्तर में पंचशील सेक्टर बी.के सड़क नं.04 नरेन्द्र वर्मा के घर से कमलेश साहू के घर तक आर.सी.सी नाली व पुलिया निर्माण लागत राशि रु.21.25 लाख एवं वार्ड क्र.51 प्रदिप्ती नगर में 80 फिट रोड में रामटेके के घर तक रोड़ व नाली निर्माण कार्य लागत राशि रु.9.81 लाख का भूमि पूजन भूमिपूजन किया गया।

महापौर ने भूमिपूजन के पश्चात कहा कि नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सड़क, नाली एवं पुलिया निर्माण से क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा, जल निकासी की व्यवस्था बेहतर बनेगी तथा आम नागरिकों को लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से राहत मिलेगी। वार्डवासियों से रूबरू हुईं महापौर, समस्याओं के शीघ्र निराकरण का दिया आश्वासन

महापौर अलका बाघमार ने वार्डवासियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। नागरिकों ने पेयजल, साफ-सफाई, सड़क एवं अन्य जनसुविधाओं से जुड़े विषयों को उनके समक्ष रखा। महापौर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के साथ-साथ जनसमस्याओं के निराकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वार्डवासियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए निगम प्रशासन लगातार क्षेत्रीय स्तर पर निगरानी कर रहा है।

सोसायटी के चावल का अवैध परिवहन करते आरोपी को सुपेला पुलिस ने वाहन सहित पकड़ा

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

थाना सुपेला पुलिस ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत वितरित किए जाने वाले सोसायटी चावल के कथित अवैध परिवहन के मामले में एक आरोपी को मालवाहक वाहन सहित पकड़ा है। मामले में खाद्य विभाग के साथ समन्वय कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 24 जून 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक नीले रंग के मालवाहक टेम्पो में सोसायटी का चावल अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने राजीव नगर ईमामबाड़ा के पास घेराबंदी कर बजाज मैक्सीमा मालवाहक वाहन क्रमांक CG 07 CV 2329 को रोककर जांच की।

जांच के दौरान वाहन में प्लास्टिक की बोरियों में कुल 14 कट्टा सोसायटी चावल मिला। पुलिस ने वाहन चालक से चावल के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा, लेकिन वह कोई संतोषजनक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सका। पूछताछ के दौरान भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने पर चालक एवं वाहन को थाना लाकर आवश्यक कार्रवाई की गई।

पुलिस ने इस मामले में सन्नी साव (28 वर्ष), निवासी पांच रास्ता, कॉन्ट्रेक्टर कॉलोनी, थाना सुपेला, जिला दुर्ग को आरोपी बनाया है। साथ ही 14 कट्टा सोसायटी चावल और बजाज मैक्सीमा मालवाहक वाहन को जब्त किया गया है। पुलिस के अनुसार, मामले में चावल के स्रोत तथा उसके परिवहन से जुड़े पहलुओं की विस्तृत जांच की जा रही है तथा खाद्य विभाग के साथ मिलकर अग्रिम वैधानिक प्रक्रिया जारी है।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी विजय यादव, प्रधान आरक्षक नवीन सिंह, आरक्षक सुरेन्द्र पटेल, गम्भीर जाट एवं चालक आरक्षक बसंत मरढ़ीया की भूमिका रही। दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि पीडीएस से संबंधित खाद्यान्न के अवैध भंडारण, परिवहन या विक्रय की जानकारी तत्काल पुलिस या संबंधित विभाग को दें, ताकि नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।

ब्रह्माकुमारीज आनंद सरोवर में मातेश्वरी जी की 61 वीं पुण्यतिथि श्रद्धा पूर्वक मनाई

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय के बघेरा स्थित "आनंद सरोवर" में संस्था के प्रथम मुख्य प्रशासिका 'ओम राधे' की 61वीं पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनायी गयी। इस अवसर पर ब्रह्माकुमारी दुर्ग से संबद्ध शहरी एवं ग्रामीण अंचल से लगभग 1500 से अधिक भाई-बहनों ने इस कार्यक्रम में शामिल हो मातेश्वरी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किये।

ब्रह्माकुमारी रीटा दीदी (संचालिका ब्रह्माकुमारीज दुर्ग) ने मातेश्वरी के जीवन वृतांत के विषय में बताया प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय का पूर्व में नाम ओम मंडली था। निराकार परमपिता परमात्मा 'शिव' ने साधारण मनुष्य तन का आधार लिया जिनका नाम दादा लेखराज था ऐसे इस संस्था की शुरुआत हुई। इसी समय संस्था में एक कन्या आयी जिनका नाम राधे था। आध्यात्मिक प्रवचन के पहले ओम का ध्वनि क्या करती थी इसलिए "ओम राधे" के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्होंने परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान को आत्मसात कर अपने जीवन को इतना परिवर्तन किया कि परमात्मा ने उन्हें संस्था में रहने वाले 350 बच्चों के आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा की पालना के निमित्त बना दिया गया और इस जिम्मेदारी को उन्होंने इतनी बखूबी से निभाया की सभी का जीवन दिव्यता संपन्न बना दिया। उनके आचरण, व्यवहार में खुद इतनी दिव्यता थी कि सभी भाई बहनें उन्हें मम्मा कहकर संबोधित करते थे। सबसे बड़ी बात उनका जन्म देने वाली मां भी उनको मम्मा ही कहती थीं।

मातेश्वरी जी कहा करती थी कि यह सृष्टि कर्म का खेत है, जहाँ हरेक मनुष्य आत्मा अपना-अपना पार्ट प्ले कर रही है, इसमें परमात्मा का भी पार्ट है लेकिन वह आत्माओं के सदृश्य जन्म-मरण में नहीं आते हैं। अभी स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा 'शिव' इस सृष्टि पर आकर ज्ञान दे रहे हैं इसलिए वतर्मान समय को पहचान कर बुद्धि रूपी नेत्र को जागृत करो तथा समय का फायदा लेकर अपनी तकदीर जगाओ । उन्हें परमात्मा की आज्ञा के प्रति सदैव इतना सम्मान रहा कि हर बात में हां जी, हां जी करती रही और अपनी इस विशेषता के कारण अध्यात्म जगत के शिखर पर आरूढ़ हो गई। कार्यक्रम के अंत में मातेश्वरी जी को भोग स्वीकार कर सभी भाई-बहनों को वरदान कार्ड दिया गया व भोग वितरित किया गया।

केसी वेणुगोपाल का छत्तीसगढ़ आगमन, वोरा ने किया स्वागत

नई दृष्टिबिंदु / अभनपुर

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव एवं सांसद केसी वेणुगोपाल के छत्तीसगढ़ आगमन पर अभनपुर में आयोजित 10 दिवसीय संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व विधायक अरुण वोरा भी उपस्थित रहे और उन्होंने वेणुगोपाल का आत्मीय स्वागत कर उनका अभिनंदन किया।

संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर में प्रदेशभर से आए जिलाध्यक्षों एवं कार्यकर्ताओं के दौरान संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने, जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने तथा कार्यकर्ताओं की भूमिका को और सशक्त करने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। अपने संबोधन में वेणुगोपाल ने कांग्रेस की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने, संगठनात्मक मजबूती तथा कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि मजबूत संगठन ही जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर सकता है।

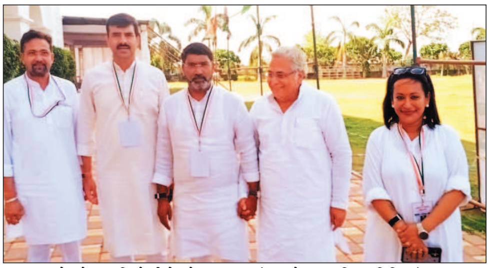

अरुण वोरा ने कहा कि केसी वेणुगोपाल का मार्गदर्शन प्रदेश कांग्रेस संगठन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके अनुभव और नेतृत्व से कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा एवं दिशा मिलेगी, जिससे संगठन और अधिक सशक्त होकर जनता के बीच अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकेगा। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह देखने को मिला तथा संगठन को मजबूत बनाने के संकल्प के साथ प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, वामसी चंद रेड्डी, सह-प्रभारी सचिव एस. संपत, जरिता लैतफलांग, विजय जांगिड़, राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम, पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम, पूर्व विधायक धनेन्द्र साहू, प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदु एवं कांग्रेसजन उपस्थित रहे।

लखनऊ अग्निकांड के बाद भिलाई नगर निगम हुआ सतर्क सिविक सेंटर के कोचिंग सेंटरों पर छापा, कई संस्थान सील

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

लखनऊ के अलीगंज स्थित एनीमेशन एवं कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 विद्यार्थियों की मौत के बाद नगर पालिक निगम भिलाई ने शहर के कोचिंग संस्थानों की जांच तेज कर दी है। निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देश पर टीम ने एजुकेशन हब सिविक सेंटर में दबिश देकर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया।

सीएसपी भी रहे साथ : निरीक्षण के दौरान सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी पुलिस टीम के साथ मौजूद रहे। निगम और पुलिस अधिकारियों ने कोचिंग संस्थानों में अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास द्वार, विद्युत सुरक्षा व्यवस्था और अन्य निर्धारित मापदंडों का जायजा लिया।

20 दिन में जानकारी देने के निर्देश: जांच टीम ने सभी संचालकों को फार्म वितरित किए हैं। इसमें संस्थानों की सुरक्षा संबंधी पूरी जानकारी भरकर 20 दिनों के भीतर निगम को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

कई संस्थान मिले असुरक्षित, किए गए सील : निरीक्षण में कुछ कोचिंग संस्थानों में आवश्यक सुरक्षा सुविधाएं नहीं मिलीं। सुरक्षा मानकों की अनदेखी को गंभीर मानते हुए निगम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ऐसे संस्थानों को सीलबंद कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

आयुक्त की चेतावनी : आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने कहा कि शहर के सभी कोचिंग एवं शिक्षण संस्थानों के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है। किसी भी तरह की लापरवाही विद्यार्थियों के जीवन को खतरे में डाल सकती है। सभी संस्थान समय सीमा में जानकारी दें और जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।

नवा रायपुर को मिली आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की नई सौगात, वित्त मंत्री चौधरी ने किया शुभारंभ

50 बिस्तरों वाले अस्पताल से नवा रायपुर और आसपास के क्षेत्र के लोगों को मिलेगा बेहतर उपचार का लाभ

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

नवा रायपुर के सेक्टर-9 में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित एक सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वित्त मंत्री ओपी चौधरी थे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री गुरु खुशवंत साहेब सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किसी भी राज्य के विकास का महत्वपूर्ण आधार होता है। नवा रायपुर में इस अत्याधुनिक अस्पताल की शुरुआत से क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और अधोसंरचना के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है,

जिससे प्रदेश के लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है।

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ आज देश के तेजी से प्रगति करने वाले राज्यों में शामिल हो चुका है। उन्होंने कहा कि एक समय जिन चुनौतियों की चर्चा होती थी, आज उन्हें पीछे छोड़ते हुए राज्य

विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रदेश में निवेश बढ़ रहा है, उद्योगों का विस्तार हो रहा है और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी निवेश और आधुनिक अस्पतालों की स्थापना से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार के प्रयासों और निजी क्षेत्र की सहभागिता से प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना लगातार मजबूत हो रही है, जिसका लाभ आम नागरिकों को मिल रहा है।

उल्लेखनीय है कि 50 बिस्तरों वाले सरोज सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अस्पताल के संचालन से नवा रायपुर सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवाओं का लाभ मिलेगा तथा उपचार के लिए दूर-दराज के शहरों पर निर्भरता कम होगी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, चिकित्सकों, अस्पताल प्रबंधन तथा बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति रही।

खास खबर

छत्तीसगढ़ में अब बिना लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम वाली यात्री बसों पर होगी कार्रवाई

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

परिवहन सचिव ने ली बस संचालको व अधिकृत वेंडरों की बैठक

छत्तीसगढ़ में यात्री सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब सभी यात्री बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) लगाना और उसे सक्रिय रखना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर नियम का पालन नहीं करने वाले बस संचालकों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम, 1988 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन सचिव एवं परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश ने इंद्रावती भवन नवा रायपुर स्थित परिवहन कार्यालय में सभी बस संचालकों एवं विभाग द्वारा वीएलटीडी लगाने हेतु अधिकृत वेंडरों की संयुक्त बैठक लेकर यात्री बसो में स्थापित वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा है कि जिन बसों में अभी तक वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) नहीं लगी है, उनमें 15 दिनों के भीतर इसे अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाए। वहीं जिन बसों में यह उपकरण लगा हुआ है लेकिन संचालित नहीं है, उन्हें तत्काल चालू किया जाए।

परिवहन विभाग के अनुसार वर्ष 2025 में राजस्थान के फलोदी और तेलंगाना के रंगारेड्डी में हुए भीषण सड़क हादसों के बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है। सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाली महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू की जा रही है। विभाग ने बताया कि राज्य मुख्यालय के कमांड एवं नियंत्रण केंद्र से सभी बसों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। उपग्रह आधारित ट्रैकिंग प्रणाली के माध्यम से यह पता लगाया जा सकेगा कि बस निर्धारित मार्ग पर चल रही है या नहीं तथा समय पर संचालन हो रहा है या नहीं। यात्रियों को भी संगवारी ऐप के जरिए बसों की वास्तविक समय की लोकेशन की जानकारी मिल सकेगी।

अतिरिक्त परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे और बुद्धिमान यातायात प्रबंधन प्रणाली स्थापित की जा रही है। इससे नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की तत्काल पहचान कर कार्रवाई की जा सकेगी। उल्लेखनीय है कि वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एक ऐसी उपग्रह आधारित प्रणाली है, जो वाहन की हर पल की स्थिति और लोकेशन की जानकारी नियंत्रण केंद्र तक पहुंचाती है। किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने में यह तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि 15 दिन की मोहलत समाप्त होने के बाद नियमों की अनदेखी करने वाले बस संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बड़ी कार्रवाई : सारंगढ़-बिलाईगढ़ में पटवारी निलंबित

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की 'सुशासन' की प्राथमिकताओं को नजरअंदाज करना एक राजस्व कर्मी को भारी पड़ गया। जिले के ग्राम झुमका में आयोजित 'सुशासन तिहार' में मिली गंभीर शिकायतों पर त्वरित एक्शन लेते हुए कलेक्टर ने पटवारी बद्रीप्रसाद साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पटवारी पर बिना मौका मुआयना और पैमाइश किए ऑनलाइन भू-नक्शा पोर्टल पर मनमाने तरीके से जमीन का बटांकन (बंटवारा) करने और आपसी विवाद की स्थिति पैदा करने का गंभीर आरोप है। मामला तब सामने आया जब ग्राम झुमका में आयोजित सुशासन तिहार के दौरान पीड़ित आवेदक ने सीधे प्रदेश के राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा को अपनी शिकायत सौंपी। इसके साथ ही कलेक्टर कार्यालय सारंगढ़ में भी इस संबंध में आवेदन दिया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने तत्काल जांच के निर्देश दिए थे।

भावी पीढ़ी के स्वास्थ्य के लिए रासायनिक खाद छोड़ अपनानी होगी जैविक खेती : नेताम

'कृषक उन्नति योजना' से किसानों को संबल- राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

अगर हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य देना है, तो रासायनिक खादों की अंधी दौड़ से बाहर निकलना होगा। धरती की उवर्रा शक्ति को बचाने और इंसानी सेहत को संवारने का एकमात्र रास्ता जैविक और प्राकृतिक खेती ही है। यह विचार प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने भाटापारा में आयोजित 'जिला स्तरीय तिलहन मेला सह जैविक कृषि कार्यशाला' के दौरान व्यक्त किए। शासकीय गजानन्द अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में संपन्न हुए इस समारोह में राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा, राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा और रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी विशेष रूप से मंच पर मौजूद रहे।

अंधाधुंध रासायनिक उपयोग पर जताई चिंता

कृषि मंत्री श्री नेताम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में 1 से 30 जून तक 'खेत चलो अभियान' चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य ध्येय किसानों को पारंपरिक और प्राकृतिक खेती की ओर वापस लाना है। छत्तीसगढ़ के 'धान का कटोरा' होने के गौरव को रेखांकित करते हुए उन्होंने चिंता जताई कि अधिक उत्पादन की लालसा में रासायनिक खादों का अंधाधुंध इस्तेमाल बढ़ गया है। इससे तात्कालिक पैदावार भले बढ़ रही हो, लेकिन यह मानव स्वास्थ्य और मिट्टी, दोनों को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे सिर्फ पारंपरिक फसलों तक सीमित न रहें, बल्कि पशुपालन, मछलीपालन और बकरी पालन को जोड़कर अपनी आय के नए स्रोत बनाएं।

किसानों को आत्मनिर्भर बनाने सरकार प्रतिबद्ध

किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार ने 'कृषक उन्नति योजना' का दायरा और बढ़ा दिया है। अब खरीफ सीजन में धान के बदले दलहन (दालें) और तिलहन (तेल बीज) की खेती करने वाले किसानों को सरकार की तरफ से 15 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि (इनपुट सब्सिडी) दी जाएगी। उन्होंने क्षेत्र के किसानों से इस योजना का बढ़-चढ़कर लाभ उठाने का आग्रह किया।

पशुधन आधारित खेती ही समृद्धि का आधार : मंत्री टंक राम वर्मा

समारोह को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का सपना जैविक खेती के जरिए ही साकार हो सकता है। उन्होंने कहा कि पुराने समय में हमारी कृषि का मूल आधार पशुधन हुआ करता था, जिससे पर्यावरण और जमीन दोनों सुरक्षित थे। आज रासायनिक खादों के कारण पानी, हवा और भोजन सब प्रदूषित हो रहे हैं। जैविक खेती से जब हमारी जमीन की सेहत सुधरेगी, तभी हमें शुद्ध अन्न मिलेगा और हमारा समाज स्वस्थ रहेगा। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल और पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा ने भी अपने विचार साझा किए।

योजनाओं के हितग्राहियों को मिला लाभ : कार्यशाला केवल विमर्श तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें शासन की कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया गया। कार्यक्रम में अतिथियों के हाथों 5 किसानों को अरहर बीज किट, 5 किसानों को नैनो यूरिया और 2 मछुआ समितियों को आधुनिक महाजाल व आइस बॉक्स का वितरण किया गया। इसके साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि और पीएम आशा योजना के तहत उत्कृष्ट काम करने वाले 5-5 किसानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष, पूर्व विधायक डॉ. सनम जांगड़े, जिला पंचायत सीईओ, सहित भारी संख्या में प्रगतिशील किसान और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

पिंक ऑटो योजना का विस्तार : 52 और महिलाओं को मिली, आत्मनिर्भरता की नई राह

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

राज्य शासन द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पिंक ऑटो प्रोजेक्ट के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी एवं मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने नवा रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में पिंक ई-ऑटो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने स्वयं ई-ऑटो में बैठकर महिलाओं का उत्साहवर्धन किया।

कार्यक्रम में द्वितीय चरण के अंतर्गत 52 महिलाओं को पिंक ई-ऑटो प्रदान किए गए। इससे पहले प्रथम चरण में 40 महिलाओं को ई-ऑटो उपलब्ध कराए गए थे। योजना की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लाभान्वित महिलाएं वतर्मान में प्रति माह 25 से 30 हजार रुपये तक की आय अर्जित कर रही हैं।

इस अवसर पर प्रथम चरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। सम्मानित महिलाओं में ग्राम राखी की श्रीमती चंद्रिका साहू, कोटराभाठा की श्रीमती शीतू कोशले, ग्राम बेंद्री की श्रीमती रेशम साहू तथा ग्राम तूता की श्रीमती ज्ञानी बैस शामिल रहीं। योजना के तहत प्रथम चरण में 14 ग्रामों और 16 ग्राम संगठनों की 40 महिलाओं को लाभ मिला था, जबकि द्वितीय चरण में 23 ग्रामों एवं 25 ग्राम संगठनों की कुल 52 महिलाओं को ई-ऑटो प्रदान किए गए हैं।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि पिंक ऑटो योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बन रही है। इस पहल से महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है और वे सम्मानजनक तरीके से आत्मनिर्भर जीवन की ओर अग्रसर हो रही हैं। उन्होंने सभी हितग्राही महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह योजना उन्हें आत्मविश्वास और नई पहचान प्रदान करेगी। कार्यक्रम में आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, एनआरडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चंदन कुमार, कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुमार बिश्वरंजन सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।

राजधानी रायपुर में मोहर्रम ताजिया जुलूस आज, शहर में ट्रैफिक डायवर्सन लागू

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मोहर्रम के अवसर पर शुक्रवार को राजधानी रायपुर में मुस्लिम समुदाय द्वारा ताजिया सवारी निकाली जाएगी। यह जुलूस शहर के विभिन्न इलाकों जैसे राजातालाब, मोमीन पारा, अमीन पारा, छोटापारा, बैजनाथपारा, नेहरू नगर और संजय नगर टिकरापारा सहित कई क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। प्रशासन के अनुसार ताजिया सवारी के दोपहर लगभग 2 बजे शुरू होने की संभावना है और यह रात करीब 10 बजे चौबे कॉलोनी स्थित करबला तालाब में संपन्न होगी।

जुलूस के सुचारू संचालन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन ने विस्तृत ट्रैफिक प्लान जारी किया है। ताजिया सवारी का प्रमुख मार्ग नुरानी चौक, ताजनगर, ईरानी डेरा, राजातालाब से शुरू होकर नुरानी चौक, पंडरी बस स्टैंड, मरहीमाता चौक, मौदहापारा, मस्जिद गली, गुरुनानक चौक, राठौर चौक, रामसागर पारा, बढ़ई पारा, मोमिन पारा, आजाद चौक, आमापारा, आरकेसी के सामने होते हुए चौबे कॉलोनी टर्निंग से करबला तालाब तक रहेगा, जहां ताजिया का विसर्जन किया जाएगा।

प्रशासन ने जुलूस के दौरान शहर में ट्रैफिक डायवर्सन लागू किया है ताकि आम नागरिकों को कम से कम असुविधा हो। पुलिस ने बताया कि जुलूस के मार्ग से जुड़े प्रमुख चौक-चौराहों पर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा और आवश्यकता अनुसार वैकल्पिक मार्गो पर डायवर्ट किया जाएगा। यातायात पुलिस द्वारा जारी प्लान के अनुसार, रायपुर शहर और जीई रोड से दुर्ग-भिलाई की ओर जाने वाले नागरिक शास्त्री चौक से महिला थाना चौक, कालीबाड़ी चौक और पचपेड़ी नाका होते हुए रिंग रोड-01 का उपयोग कर आवागमन कर

सकेंगे। इसी तरह शास्त्री चौक से जीई रोड पर चलने वाली सिटी बसों को भी शास्त्री चौक से जयस्तंभ चौक की ओर न भेजकर कालीबाड़ी चौक और पचपेड़ी नाका मार्ग से रिंग रोड-01 की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

टाटीबंध से शहर की ओर आने वाले वाहनों को टाटीबंध चौक से रिंग रोड-01 की ओर मोड़ा जाएगा। वहीं जीई रोड पर एनआईटी के पास डंगनिया और गोल चौक जाने वाले मार्ग को भी वैकल्पिक मार्गो से जोड़ा जाएगा। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि जुलूस के दौरान मुख्य मार्गो पर भारी वाहनों और सामान्य ट्रैफिक को नियंत्रित किया जाए। इसके अलावा शहर के पुरानी बस्ती, लाखेनगर और आसपास के क्षेत्रों से सुंदर नगर, डंगनिया और दुर्ग-भिलाई जाने वाले नागरिकों को कालीबाड़ी से संतोषीनगर और जलगृह मार्ग होते हुए भाठागांव चौक के रास्ते आवागमन करने की सलाह दी गई है।

ताजिया जुलूस के दौरान जीई रोड पर आजाद चौक से आश्रम तिराहा और चौबे कॉलोनी टर्निंग तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित रहेगी। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक इस मार्ग का उपयोग न करें और वैकल्पिक मार्गो का ही उपयोग करें। पुलिस और प्रशासन ने यह भी कहा है कि पूरे जुलूस मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी और जगह-जगह पुलिस बल की तैनाती की जाएगी ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। साथ ही यातायात पुलिस लगातार निगरानी रखेगी और आवश्यकता अनुसार ट्रैफिक को नियंत्रित करेगी। शहर प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि धार्मिक आयोजन को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने में सभी लोग सहयोग करें ताकि किसी को असुविधा न हो।

केन्द्रीय मंत्री व मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं और किसानों के लिए खाद-बीज उपलब्धता पर की चर्चा

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान जनस्वास्थ्य, चिकित्सा अधोसंरचना, औषधि एवं उर्वरक क्षेत्र सहित विभिन्न विभागीय और समसामयिक विषयों पर विस्तृत एवं सार्थक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। विशेष रूप से दूरस्थ, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और अन्य चिकित्सा संस्थानों को मजबूत बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के नागरिकों को बेहतर उपचार और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं अपने ही राज्य में उपलब्ध हों।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि और उर्वरक क्षेत्र से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की। उन्होंने केंद्रीय

मंत्री को जानकारी दी कि राज्य में किसानों को खाद और बीज की पर्याप्त एवं समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े तथा खरीफ सीजन के दौरान आवश्यक कृषि आदानों की आपूर्ति सुचारु रूप से बनी रहे। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि खाद वितरण व्यवस्था पर सतत निगरानी रखी जाए और किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, जमाखोरी अथवा लापरवाही को कतई बर्दाश्त न किया जाए। साथ ही गांव-गांव अभियान चलाकर किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने तथा नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री को यह भी अवगत कराया कि राज्य सरकार नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। किसानों को इनके लाभों की जानकारी देने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि खेती में उत्पादन क्षमता बढ़े, लागत कम हो और कृषि अधिक लाभकारी बन सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार भारत सरकार के पूर्ण सहयोग से स्वास्थ्य, कृषि और जनकल्याण के क्षेत्रों में विकास को नई गति देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। राज्य के समग्र विकास के लिए केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय को और मजबूत किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री श्री जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, किसानों के हित में उठाए जा रहे कदमों तथा जनकल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने स्वास्थ्य एवं अन्य विकासात्मक क्षेत्रों में केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।

भारत की पोलियो मुक्त रखेंगे बरकरार : धमतरी जिले में 28 जून से महाअभियान

देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने और भविष्य की पीढ़ी को इस गंभीर बीमारी से सुरक्षित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में 28 से 30 जून 2026 तक राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष अभियान का मुख्य नारा दो बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार तय किया गया है।स्वास्थ्य विभाग ने इस तीन दिवसीय अभियान के दौरान जिले के 0 से 5 वर्ष तक की आयु के सभी पात्र बच्चों को कवर करने के लिए कमर कस ली है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला टीकाकरण अधिकारी ने संयुक्त रूप से बताया कि जिले में इस बार 1 लाख 10 हजार 443 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। शत-प्रतिशत कवरेज के लिए जिले भर के आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत भवनों और उप स्वास्थ्य केंद्रों में 756 पोलियो बूथ बनाए गए हैं। अभियान को सफल बनाने के लिए 1,915 स्वास्थ्य और मैदानी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। ईंट-भट्ठों, कोयला भट्ठों, निर्माण स्थलों, बस स्टैंड, रेलवे प्लेटफॉर्म और घुमंतू परिवारों जैसे उच्च जोखिम (भ्पही-त्पा) वाले क्षेत्रों के लिए 29 विशेष मोबाइल और ट्रांजिट टीमें गठित की गई हैं, जिनमें 68 सदस्य मुस्तैद रहेंगे।

स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार अभियान के पहले दिन यानी 28 जून को सभी निर्धारित बूथों पर बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। इसके बाद, जो बच्चे किसी कारणवश बूथ तक नहीं पहुंच पाएंगे, उनके लिए 29 और 30 जून को स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर सर्वे करेंगी। छूटे हुए बच्चों को मौके पर ही दवा पिलाई जाएगी और घरों पर अनिवार्य रूप से चिन्हांकन (मार्किंग) किया जाएगा। स्वास्थ्य अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यद्यपि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को वर्ष 2014 में ही पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है, लेकिन पड़ोसी देशों पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी वाइल्ड पोलियो वायरस सक्रिय है। अंतर्राष्ट्रीय आवागमन के कारण संक्रमण का खतरा हमेशा बना रहता है, जिसके चलते देश की सुरक्षात्मक दीवार को मजबूत रखना बेहद जरूरी है।

संपादकीय

सवाल तो यह है जो हुआ गलत हुआ आगे न हो

राम मंदिर हिंदू समाज के लोगों के लिए आस्था के एक बड़े केंद्र के रूप में सामने आया है और इससे हिंदू समाज में एकजुट हुआ है। यह आने वाले दिनों में जितना बड़ा आस्था का केंद्र बनेगा उतना ही हिंदू समाज एकजुट होगा और हिंदुत्व की राजनीति करने वाले दलों संगठनों को इसका आर्थिक,सामाजिक व राजनीतिक लाभ होगा।मोटे तौर पर अयोध्या का मंदिर बन जाने से क्षेत्र का हर तरह के विकास हुआ है। क्षेत्र में कई तरह के रोजगार लोगों को मिले हैं, इससे क्षेत्र के लोगों की आय बढ़ी है और अयोध्या के कारण यूपी की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है।यानी आम लोगों को भी लाभ हुआ है और सरकार को भी लाभ हुआ है। अयोध्या के विकास का काम सरकार ने जितने अच्छे से किया। मंदिर बनाने का काम जितने अच्छे से हुआ .मंदिर बन जाने के बाद दान व चढ़ावे के प्रबंधन की व्यवस्था की और जितनी गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत थी, न तो ट्रस्ट ने ध्यान दिया। न ही सरकार ने ध्यान दिया।

मंदिर में चढ़ावे व दान के प्रबंधन की व्यवस्था की पोल चढ़ावे की चोरी की एसआईटी जांच के बाद खुल रही है कि दान व चढ़ावे के प्रबंधन की व्यवस्था में कितनी खामियां थी, सबसे बड़ी खामी तो यह है कि दान व चढ़ावे को कोई साक्ष्य ही नही है कि किसने क्या दान किया,कब दान किया, क्या दान किया। सुरक्षा व पारदर्शिता के लिए जो सीसीटीवी लगाए गए थे उसमें ऐसी व्यवस्था की गई थी कि सीसीटीवी फुटेज कितनी भी अहम हो वह 45 दिन बाद डिलीट हो जाती थी। यानी दान,चढ़ावे, रुपए की गिनती में कोई गड़बड़ी की गई है तो उसका कोई सबूत नहीं है। एसआईटी का जांच के लिए सिर्फ 45 दिन के सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। यानी गड़बड़ी करने वालों ने जो गड़बड़ी की है,उसका कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है।एसआईटी ने अपनी पहली रिपोर्ट सौंप दी है, उसमे चंपत राय समेत 17 लोगों की भूमिका को संदिग्ध बताया गया है।

लोगों को सबसे बुरा यह जानकर लग रहा है कि एसआईटी को यह पता नहीं चल रहा है कि चढ़ावा आया कितना है और चोरी कितना हुआ है।मंदिर बन जाने के बाद करोड़ों लोगों ने अयोध्या मंदिर जाकर रामलला के दर्शन किए हैं। इससे करोड़ों का चढ़ावा मंदिर में आया है।बेतहाशा चढ़ावा आने के कारण मंदिर व्यवस्था मे लगे लोगों को प्रबंधन ठीक न होने के कारण लगा होगा कि वह इसमें चोरी कर सकते हैं और प्रबंधन की खामी के कारण ही चढ़ावे की चोरी हुई है। जो हो गया है इसका सबूत मिलने पर दोषी लोगों को सजा दिलाई जा सकती है लेकिन कोई सबूत न मिले तो किसे सजा दी जाएगी। मामला अदालत में जाएगा तो अदालत को सबूत देखेगी और बिना सबूत के किसी को सजा तो मिलने से रही।

अब यह तो साफ हो गया है कि अयोध्या मंदिर में चढ़ावे व दान की चोरी व्यवस्था की खामी के कारण हुई है। अब वक्त इस व्यवस्था को सुधारने का है। अयोध्या में तकनीक से ही ऐसी व्यवस्था की सकती है कि चढ़ावे व दान में चोरी की कोई गुंजाइश ही न रहे।अभी कुछ व्यवस्था में सुधार शुरू हो गया है। जैसे सीसीटीवी फुटेज को अब 180 दिनों तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। बैकों नगदी भेजे जाने वाले बक्से में पहले एक ताला लगाया जाता था अब दो ताले की व्यवस्था की गई ताकि कोई एक व्यक्ति रास्ते में उसे खोल न सके।अयोध्या ही नहीं देश के ज्यादातर बड़े धार्मिक स्थलों में चढ़ावे व दान के रखरखाव की वही पुरानी पद्धति काम में लाई जा रही है,अभी तो हुंडी में डालों, बाद में खोलकर गिनती कर ली जाएगी कि कितना चढ़ावा आया।अब तो मशीन आ गई जिसमें पैसा जमा किया जा सकता है।मंदिर में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि बड़े दानदाता को तुरंत मशीन से रसीद मिल जाए कि उसने कितना दान किया है, किस तारीख को दान किया है। इसमें तो रोज का रोज हिसाब हो सकता है कि कितना चढ़ावा आया और उसकाआनलाइन हिसाब रखा जा सकता है।

ज्यादा दान देने वालों के लिए कैमरा रिकार्डिंग की व्यवस्था की जा सकती है।अच्छा तो यह हो कि रोज जितना दान आया उसे देश के लोग किसी पोर्टल पर देख भी सकें।अयोध्या में मंदिर में एक बार गड़बड़ी होने से लोगो का भरोसा कहीं कम तो हुआ है कि उसके दान की चोरी हो सकती है। इस भरोसे को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि लोग दान करें तो लगे कि अब वह चोरी नहीं हो सकता। इससे ट्रस्ट पर भी कोई आरोप नही लगाएगा। जब दान मे बहुत पैसा आता है तो वह व्यक्ति आस्था का सवाल नहीं रह जाता है,वह सार्वजनिक धन हो जाता है और सार्वजनिक धन एक जवाबदेही है। न तो उसका दुरुपयोग होना चाहिए और न ही चोरी होना चाहिए।

हमारे देश में ऐसा विषय नहीं है जिस पर हमारे देश के राजनीतिक दल राजनीति नहीं कर सकते। ऐसे दल भी हैं जिनकी राम मंदिर व रामलला के प्रति कोई आस्था नहीं है लेकिन चढावा चोरी हो गया है तो उनको राजनीति करनी है, इसलिए राजनीति करनी है कि वह समझते हैं कि इससे वह यूपी के चुनाव में राजनीतिक लाभ उठा सकते हैं।हकीकत में जो दल भी अयोध्या में चोरी का मामला उठा रहे है उनकी मंशा हकीकत में सतातन का विरोध है, सनातन को बदनाम करना है।अयोध्या से सनातन का विस्तार हो रहा है और उनको पिछले 12 साल से इसका नुकसान हो रहा है, इसलिए वह सनातन का अपमान कर सनातन के प्रति बढ़ रहे भरोसे को कम करना चाहते हैं। ट्रस्ट पर सरकार, भाजपा ने भरोसा किया था वह भरोसे पर खरा नहीं उतरा। अब योगी सरकार खामी पता चलने के बाद व्यवस्था को सुधारने का काम करेगी और ऐसी व्यवस्था करेगी की दोबारा चढ़ावा व दान चोरी न हो।

पचपदरा रिफाइनरी : भारत के दुबई का सपना साकार होने की ओर

गोपेन्द्र नाथ भट्ट

राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र बाड़मेर में स्थित पचपदरा रिफाइनरी परियोजना एक बार फिर चर्चा में है। देश की सबसे बड़ी ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल परियोजनाओं में शामिल यह महत्वाकांक्षी योजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 4 जुलाई 2026 में इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। पिछले वर्ष उद्घाटन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं, लेकिन परियोजना परिसर में हुई आगजनी की घटना के कारण कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा था। अब सुरक्षा और तकनीकी मानकों की पुन: समीक्षा के बाद उद्घाटन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं।

पचपदरा रिफाइनरी को केवल एक औद्योगिक परियोजना के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे पश्चिमी राजस्थान की आर्थिक तस्वीर बदलने वाले विकास मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यही कारण है कि इसे ह्लभारत का दुबईह्व बनाने की अवधारणा से जोड़ा जा रहा है। जिस प्रकार दुबई ने तेल और पेट्रोकेमिकल उद्योग के आधार पर वैश्विक व्यापारिक केंद्र का रूप लिया, उसी प्रकार पचपदरा क्षेत्र भी आने वाले वर्षों में ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक निवेश का प्रमुख केंद्र बन सकता है।

करीब 72 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली यह परियोजना संयुक्त उपक्रम के रूप में विकसित की गई है। इसमें राजस्थान सरकार तथा एच पी सी एल की महत्वपूर्ण भागीदारी है। प्रतिवर्ष लगभग 90 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल के शोधन की क्षमता वाली यह रिफाइनरी देश की आधुनिकतम रिफाइनरियों में गिनी जाएगी। इसके साथ ही पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी विकसित किया गया है, जिससे केवल ईंधन उत्पादन तक सीमित न रहकर प्लास्टिक, रसायन और अन्य औद्योगिक उत्पादों का निर्माण भी संभव होगा।

राजस्थान के लिए इस परियोजना का महत्व कई कारणों से विशेष है। राज्य लंबे समय से खनिज संसाधनों में समृद्ध होने के बावजूद बड़े औद्योगिक निवेश की दृष्टि से अपेक्षाकृत पिछड़ा माना जाता रहा है। पचपदरा रिफाइनरी के संचालन में आने से हजारों प्रत्यक्ष और लाखों अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। स्थानीय युवाओं को तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी। साथ ही बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर और जैसलमेर जैसे क्षेत्रों में सहायक उद्योगों का विकास भी तेज होगा।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की सरकार इस परियोजना को विकसित राजस्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देख रही है। राज्य सरकार का मानना है कि रिफाइनरी शुरू होने के बाद राजस्थान की औद्योगिक विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और राज्य को कर राजस्व के रूप में भी बड़ा लाभ मिलेगा। यही कारण है कि परियोजना से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं, सड़क संपर्क, रेल नेटवर्क और औद्योगिक कॉरिडोर के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

पिछले वर्ष हुई आगजनी की घटना ने परियोजना प्रबंधन के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी थीं। यद्यपि नुकसान सीमित था, लेकिन सुरक्षा कारणों से उद्घाटन कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ा। इसके बाद विस्तृत तकनीकी जांच और सुरक्षा ऑडिट कराए गए। अब अधिकांश कार्य पूरे हो चुके हैं और उत्पादन प्रारंभ करने की दिशा में अंतिम तैयारियां चल रही हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि पचपदरा रिफाइनरी केवल ऊर्जा उत्पादन का केंद्र नहीं होगी, बल्कि यह पश्चिमी राजस्थान में शहरीकरण और आर्थिक गतिविधियों का नया अध्याय लिखेगी। आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और सेवा क्षेत्रों में भी बड़े निवेश की संभावनाएं बन रही हैं। क्षेत्र में भूमि मूल्यों में वृद्धि और नए व्यावसायिक अवसरों का विस्तार पहले से दिखाई देने लगा है।

राजनीतिक दृष्टि से भी यह परियोजना महत्वपूर्ण है। इसकी आधारशिला वर्ष 2013 में रखी गई थी और बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में इसका पुनः शिलान्यास किया था। लंबे समय तक चली निर्माण प्रक्रिया के बाद अब इसका उद्घाटन होना केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जाएगा।

कुल मिलाकर, पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन केवल एक औद्योगिक इकाई का शुभारंभ नहीं होगा, बल्कि यह राजस्थान के आर्थिक इतिहास में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक बनेगा। यदि अपेक्षाओं के अनुरूप निवेश और औद्योगिक गतिविधियां विकसित होती हैं, तो आने वाले वर्षों में बाड़मेर का यह मरुस्थलीय क्षेत्र वास्तव में ह्लभारत के दुबईह्व के रूप में अपनी नई पहचान स्थापित कर सकता है।

ईरान, होर्मुज और बदलती विश्व व्यवस्था

महेन्द्र तिवारी

विश्व राजनीति में शक्ति का अर्थ समय के साथ निरंतर बदलता रहा है। इतिहास के विभिन्न कालखंडों में शक्ति के मानक बदलते रहे हैं। कभी विशाल और अजेय सेनाएँ किसी साम्राज्य या देश की ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती थीं, तो कभी औद्योगिक क्रांति के बाद औद्योगिक उत्पादन और आर्थिक क्षमता को वैश्विक शक्ति का मुख्य आधार समझा गया। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, विशेषकर शीतयुद्ध के दौर में, परमाणु हथियारों को सर्वोच्च शक्ति और संप्रभुता का प्रतीक माना जाने लगा। ऐसा माना जाता था कि परमाणु क्षमता से संपन्न देश ही वैश्विक व्यवस्था की दिशा तय कर सकते हैं। किंतु 21वीं शताब्दी के आगमन ने इन सभी पारंपरिक धारणाओं को पीछे छोड़ दिया है। आज के दौर में वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति, तकनीकी नेटवर्क और समुद्री मार्गों ने शक्ति की परिभाषा को एक बिल्कुल नया और बहुआयामी स्वरूप प्रदान किया है। हाल के वर्षों में ईरान और पश्चिमी देशों के बीच बढ़े तनाव तथा होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर उभरी परिस्थितियों ने यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि आधुनिक दुनिया में केवल सैन्य सामर्थ्य ही निर्णायक नहीं है। किसी महत्वपूर्ण भौगोलिक मार्ग, संसाधन अथवा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर नियंत्रण भी उतना ही प्रभावशाली और रणनीतिक साधन बन सकता है। यही वह महत्वपूर्ण संदेश है जो ईरान की वर्तमान रणनीति के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने उभरकर आया है।

होर्मुज जलडमरूमध्य पश्चिम एशिया का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील समुद्री मार्ग है। भौगोलिक दृष्टि से यह फारस की खाड़ी को अरब सागर और हिंद महासागर से जोड़ता है। इस संकरे मार्ग का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात जैसे दुनिया के सबसे प्रमुख तेल उत्पादक देशों का समुद्री निर्यात इसी मार्ग से होकर गुजरता है। वैश्विक कच्चे तेल की कुल आपूर्ति का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा रोजाना इस संकरे जलमार्ग से दुनिया के विभिन्न हिस्सों तक पहुँचता है। इसके अलावा, तरल प्राकृतिक गैस के वैश्विक समुद्री व्यापार का भी एक बहुत बड़ा भाग इसी रास्ते से तय होता है। इसलिए होर्मुज केवल एक साधारण जलमार्ग नहीं है, बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन है। यदि इस मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है या तनाव बढ़ता है, तो उसका सीधा और तात्कालिक प्रभाव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा की कीमतों, समुद्री परिवहन लागत, औद्योगिक उत्पादन और दुनिया भर के उपभोक्ता बाजारों पर दिखाई देने लगता है।

इस पूरे परिदृश्य में ईरान की भौगोलिक स्थिति उसे इस क्षेत्र में एक विशिष्ट सामरिक महत्व प्रदान करती है। इस जलडमरूमध्य के उत्तरी तट पर ईरान का सीधा भौगोलिक प्रभाव है और इसी कारण वह लंबे समय से इस मार्ग को अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक शक्ति के रूप में देखता रहा है। जब भी पश्चिमी देशों द्वारा ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए या उसकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं की अनदेखी की गई, तब उसने बार-बार यह संकेत दिया कि वह होर्मुज में जहाजों के आवागमन को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। कई अवसरों पर ईरान ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह चेतावनी भी दी है कि यदि उसके राष्ट्रीय हितों को गंभीर नुकसान पहुँचाया गया, तो वह इस मार्ग को पूरी तरह बंद करने अथवा यहाँ अतिरिक्त नियंत्रण स्थापित करने पर विचार कर सकता है। यहीं से दुनिया के लिए एक नया भू-राजनीतिक संदेश निकलता है कि आधुनिक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में भूगोल स्वयं एक बहुत बड़ी शक्ति है। यदि किसी देश के पास कोई ऐसा विशिष्ट स्थान है जो वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति या सामरिक गतिविधियों के लिए अनिवार्य है, तो वह देश अपनी सीमित सैन्य या आर्थिक क्षमताओं के बावजूद वैश्विक मंच पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव रख सकता है। ईरान दशकों से भारी आर्थिक प्रतिबंधों और राजनीतिक दबावों का सामना कर रहा है, लेकिन होर्मुज पर उसकी सामरिक स्थिति उसे विश्व राजनीति में लगातार प्रासंगिक और शक्तिशाली बनाए रखती है।

यह स्थिति पारंपरिक शक्ति संतुलन को भी गंभीर चुनौती देती है। लंबे समय तक वैश्विक राजनीति में यह माना जाता रहा कि बड़ी सैन्य और परमाणु शक्ति रखने वाले देश किसी भी क्षेत्रीय संकट का समाधान अपने पक्ष में करने में सक्षम होते हैं। लेकिन होर्मुज का उदाहरण दिखाता है कि कठोर भौगोलिक वास्तविकताएँ कई बार विशाल सैन्य शक्ति को भी सीमित कर देती हैं। यदि इस समुद्री मार्ग पर थोड़ा भी तनाव बढ़ता है तो उसका असर केवल एक क्षेत्र पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। इसलिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों को भी यहाँ किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई करने से पहले कूटनीति, समझौतों और क्षेत्रीय संतुलन का सहारा लेना पड़ता है। इसके साथ ही, ईरान की इस रणनीति ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के प्रश्न को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है। ऊर्जा आधुनिक अर्थव्यवस्था की आधारशिला है जिसके बिना उद्योग, परिवहन, कृषि और संचार जैसे लगभग सभी क्षेत्र ठप हो सकते हैं। जब किसी ऐसे महत्वपूर्ण मार्ग पर संकट की मामूली आशंका भी उत्पन्न होती है, तब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतों में तेजी से उतार-चढ़ाव शुरू हो जाता है। इससे दुनिया भर के निवेशकों में चिंता बढ़ती है और सरकारें वैकल्पिक व्यवस्थाओं की तलाश करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। इस प्रकार एक सीमित क्षेत्रीय तनाव भी व्यापक वैश्विक आर्थिक अस्थिरता का कारण बन सकता है।

इस परिस्थिति का प्रभाव केवल तेल उत्पादक या पश्चिमी देशों तक सीमित नहीं रहता है। जापान, दक्षिण कोरिया, भारत और यूरोप के अनेक प्रमुख देश अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से पश्चिम एशिया के इसी मार्ग पर निर्भर हैं। यदि होर्मुज में कोई बाधा आती है तो इन विकासशील और विकसित देशों की ऊर्जा सुरक्षा सीधे प्रभावित होती है। यही कारण है कि दुनिया के तमाम राष्ट्र इस मार्ग को हमेशा खुला और सुरक्षित बनाए रखने के पक्षधर हैं। वे अच्छी तरह समझते हैं कि यहाँ उत्पन्न होने वाला कोई भी संकट उनके घरेलू आर्थिक हितों को सीधे चोट पहुँचाएगा। ईरान के इस व्यवहार से यह भी स्पष्ट होता है कि भविष्य की प्रतिस्पर्धा केवल हथियारों के संचय की नहीं होगी। बीते दशकों में परमाणु हथियारों के प्रसार को लेकर व्यापक चिंताएँ व्यक्त की जाती रही हैं, लेकिन आज एक नई प्रवृत्ति उभरती दिखाई दे रही है जिसमें देश उन स्थानों, संसाधनों और मार्गों पर नियंत्रण की तलाश कर रहे हैं जिनके माध्यम से वे संपूर्ण वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित कर सकें। इन्हें भू-राजनीति की भाषा में चोक प्वाइंट कहा जाता है, जहाँ से होकर व्यापार, ऊर्जा या संचार का बड़ा भाग गुजरता है।

दुनिया में होर्मुज अकेला ऐसा मार्ग नहीं है। मलक्का जलडमरूमध्य पूर्वी एशिया और हिंद महासागर के बीच व्यापार का अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है, जहाँ से वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग एक तिहाई हिस्सा गुजरता है। इसी तरह बाब-अल-मंदेब लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है जो यूरोप तथा एशिया के बीच व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है, और स्वेज नहर को वैश्विक परिवहन की जीवनरेखा माना ही जाता है। यदि इन सभी मार्गों में कहीं भी रुकावट आती है तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। विश्लेषकों को चिंता है कि ईरान का यह सफल उदाहरण अन्य क्षेत्रीय देशों को भी इसी प्रकार की रणनीति अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे वैश्विक व्यापार अधिक अनिश्चित और अस्थिर हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग के स्थान पर प्रतिस्पर्धा और दबाव की राजनीति बढ़ सकती है। इस संदर्भ में चीन जैसी महाशक्ति की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसने तकनीकी आपूर्ति श्रृंखलाओं, दुर्लभ खनिजों और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के क्षेत्र में अपना प्रभाव अत्यधिक बढ़ा लिया है। यदि ऊर्जा मार्गों की असुरक्षा बढ़ती है, तो कई देश जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करके नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों की ओर बढ़ेंगे, जिससे उन तकनीकों पर नियंत्रण रखने वाले देशों का महत्व और अधिक बढ़ जाएगा। इस प्रकार एक प्रकार की निर्भरता समाप्त होते ही दूसरी निर्भरता जन्म ले लेगी।

यह पूरी स्थिति वैश्वीकरण की उस पारंपरिक अवधारणा को भी चुनौती देती है जिसके अनुसार वस्तुओं, सेवाओं और पूँजी का प्रवाह स्वतंत्र और निर्बाध होना चाहिए। लेकिन जब इन महत्वपूर्ण मार्गों और आपूर्ति श्रृंखलाओं का उपयोग राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में होने लगता है, तब वैश्वीकरण की नींव कमजोर पड़ने लगती है। कंपनियों और सरकारों को वैकल्पिक मार्गों, अतिरिक्त भंडारण और विविध स्रोतों की महँगी व्यवस्था करनी पड़ती है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है। हालांकि ईरान का तर्क है कि वह केवल अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपनी भौगोलिक स्थिति का उपयोग एक रणनीतिक साधन के रूप में करता है, जबकि आलोचक इसे वैश्विक स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा मानते हैं। इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच संतुलन बनाने के लिए अब कूटनीति की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। केवल सैन्य शक्ति या आर्थिक प्रतिबंध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं दे सकते। यदि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा को अक्षुण्ण रखना है, तो क्षेत्रीय देशों तथा बड़ी शक्तियों के बीच निरंतर संवाद और सहयोग आवश्यक होगा। अंततः, ईरान के व्यवहार से यही निष्कर्ष निकलता है कि 21वीं शताब्दी में शक्ति का स्वरूप बहुआयामी हो गया है, जहाँ भौगोलिक स्थिति, समुद्री मार्ग, संसाधन और ऊर्जा नेटवर्क ही भविष्य की विश्व राजनीति की दिशा तय करेंगे।

लखनऊ कोचिंग अग्निकांड: क्या हमारे बच्चों की सुरक्षा सिर्फ खबर बनकर रह जाएगी?

डॉ. सत्यवान सौरभ

लखनऊ में हुए हालिया कोचिंग अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। धुएँ से घिरी इमारतें, चीखते-बिलखते विद्यार्थी, घबराए हुए अभिभावक और राहत-बचाव दलों की भागदौड़—ये दृश्य केवल एक दुर्घटना की तस्वीर नहीं हैं, बल्कि हमारी व्यवस्था की उन कमजोरियों का आईना हैं जिन्हें हम वर्षों से अनदेखा करते आ रहे हैं। हर बार किसी बड़े हादसे के बाद कुछ दिनों तक शोक, संवेदना और आक्रोश दिखाई देता है, फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे बच्चों की सुरक्षा केवल कुछ दिनों की खबर बनकर रह जाएगी? क्या हम तब तक जागेंगे नहीं, जब तक अगली त्रासदी किसी और शहर में, किसी और कोचिंग संस्थान या हॉस्टल में घटित नहीं हो जाती?

आज भारत में लाखों विद्यार्थी अपने घरों से दूर रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। कोटा, दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज, पटना, जयपुर और चंडीगढ़ जैसे शहर शिक्षा के बड़े केंद्र बन चुके हैं। अभिभावक अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदों के साथ उन्हें इन संस्थानों में भेजते हैं। वे फीस भरते हैं, हॉस्टल का खर्च उठाते हैं और यह भरोसा करते हैं कि जहां उनका बच्चा पढ़ रहा है, वहां उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। दुर्भाग्य से यह भरोसा कई बार टूट जाता है।

ऐसे हादसे अचानक नहीं होते। इनके पीछे वर्षों की लापरवाही, नियमों की अनदेखी और जवाबदेही की कमी होती है। जब किसी इमारत में पर्याप्त आपातकालीन निकास नहीं होते, जब बिजली की वायरिंग मानकों के अनुरूप नहीं होती, जब फायर एक्सटिंग्विशर केवल दिखावे के लिए लगाए जाते हैं, जब भवन निर्माण नियमों को ताक पर रखकर व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जाती हैं, तब किसी भी दिन एक छोटी-सी चिंगारी बड़ी त्रासदी का रूप ले सकती है।

इस घटना के बाद सबसे पहला प्रश्न अभिभावकों को स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या उन्होंने कभी अपने बच्चे के कोचिंग संस्थान, हॉस्टल या पीजी की सुरक्षा व्यवस्था की वास्तविक जांच की है? अक्सर हम संस्थान की प्रतिष्ठा, परिणाम और सुविधाओं के बारे में पूछते हैं, लेकिन सुरक्षा संबंधी प्रश्नों को नजरअंदाज कर देते हैं। यह प्रवृत्ति बदलनी होगी। बच्चे के भविष्य जितना महत्वपूर्ण है, उसका जीवन और सुरक्षा उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

अभिभावकों को सबसे पहले आपातकालीन निकास की स्थिति की जांच करनी चाहिए। किसी भी भवन में आग लगने की स्थिति में सुरक्षित निकास जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर साबित हो सकता है। कई संस्थानों में आपातकालीन सीढ़ियां या तो बंद रहती हैं या उनमें सामान भरा रहता है। कुछ जगहों पर सुरक्षा द्वारों पर ताले लगे होते हैं। ऐसी स्थिति में भगदड़ और अफरा-तफरी के दौरान बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाता है। यदि किसी भवन में आपातकालीन निकास स्पष्ट रूप से चिन्हित नहीं हैं या उनके उपयोग में कोई बाधा है, तो उसे गंभीर चेतावनी समझना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता और कार्यशीलता है। फायर एक्सटिंग्विशर केवल दीवारों पर टांग देने से सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती। उनकी नियमित जांच, रखरखाव और समय-समय पर रिफिलिंग आवश्यक है। अभिभावकों को यह जानने का अधिकार है कि संस्थान में कितने अग्निशमन यंत्र हैं, उनकी वैधता क्या है और क्या स्टाफ को उनके उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया है। यदि कोई संस्थान इन सवालों के स्पष्ट उत्तर नहीं देता, तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर संदेह होना चाहिए।

तीसरा मुद्दा फायर एनओसी यानी अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाणपत्र का है। हमारे देश में अक्सर देखा गया है कि कागजों पर सभी नियम पूरे दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति

अलग होती है। कई बार निरीक्षण केवल औपचारिकता बनकर रह जाता है। इसलिए केवल एनओसी की प्रति देखना पर्याप्त नहीं है। उसकी वैधता, निरीक्षण रिपोर्ट और सुरक्षा मानकों की वास्तविक स्थिति की भी जांच आवश्यक है। प्रशासन को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि फायर एनओसी केवल कागजी प्रक्रिया न रह जाए, बल्कि वास्तविक सुरक्षा का प्रमाण बने। इमारत की संरचना भी सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कई कोचिंग संस्थान संकरी गलियों में स्थित बहुमंजिला इमारतों में संचालित होते हैं। इनमें पर्याप्त वेंटिलेशन नहीं होता, खिड़कियां सीमित होती हैं और भीड़ क्षमता से कहीं अधिक होती है। ऐसी इमारतें दुर्घटना की स्थिति में मौत के जाल में बदल सकती हैं। इसलिए भवन निर्माण मानकों का पालन सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।

सुरक्षा केवल उपकरणों से नहीं आती, बल्कि तैयारी से भी आती है। क्या संस्थान नियमित फायर ड्रिल आयोजित करता है? क्या विद्यार्थियों को बताया जाता है कि आपातकाल की स्थिति में क्या करना है? क्या स्टाफ को प्राथमिक आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया है? इन प्रश्नों के उत्तर अक्सर नकारात्मक होते हैं। जबकि विकसित देशों में स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में नियमित सुरक्षा अभ्यास अनिवार्य होता है। भारत में भी यह व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। यह समस्या केवल कोचिंग संस्थानों तक सीमित नहीं है। हॉस्टल, पीजी, छात्रावास और निजी आवासीय व्यवस्थाएं भी अक्सर सुरक्षा मानकों की अनदेखी करती हैं। अनेक स्थानों पर क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को रखा जाता है। संकरी सीढ़ियां, बंद खिड़कियां और खराब विद्युत व्यवस्था जोखिम को कई गुना बढ़ा देती हैं। इसलिए सुरक्षा का दायरा व्यापक रूप से देखा जाना चाहिए।

प्रशासन की भूमिका भी इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुर्घटना के बाद जांच समिति गठित करना और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा करना पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि नियमित निरीक्षण और कठोर निगरानी की व्यवस्था विकसित की जाए। प्रत्येक शहर में कोचिंग संस्थानों और छात्रावासों का वार्षिक सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य होना चाहिए। जिन संस्थानों में गंभीर खामियां पाई जाएं, उन्हें सुधार तक संचालन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके साथ ही स्थानीय निकायों और अग्निशमन विभाग को तकनीकी संसाधनों और मानवबल से मजबूत बनाना होगा। कई बार दुर्घटना के दौरान फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंच पाती। संकरी गलियां, ट्रैफिक और अपर्याप्त संसाधन राहत कार्यों को प्रभावित करते हैं। यदि हम वास्तव में ऐसी घटनाओं को रोकना चाहते हैं, तो आपातकालीन सेवाओं को अधिक सक्षम बनाना होगा।

समाज और मीडिया की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। मीडिया को केवल सनसनीखेज तस्वीरें दिखाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसे उन कारणों की गहराई से पड़ताल करनी चाहिए जो ऐसी घटनाओं को जन्म देते हैं। वहीं समाज को भी सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त करने से आगे बढ़कर सक्रिय भागीदारी करनी होगी। अभिभावक संगठनों, नागरिक समूहों और सामाजिक संस्थाओं को सुरक्षा मानकों की निगरानी और जागरूकता अभियान में भाग लेना चाहिए। आज आवश्यकता एक सामूहिक आंदोलन की है। जिस प्रकार स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जन-जागरूकता अभियान चलाए गए, उसी प्रकार शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा को लेकर भी व्यापक अभियान की जरूरत है। प्रत्येक अभिभावक, प्रत्येक छात्र और प्रत्येक नागरिक को यह समझना होगा कि सुरक्षा कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं, बल्कि मौलिक अधिकार है।

सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम अक्सर हादसों से सीखते नहीं हैं। दिल्ली, सूरत, राजकोट, कोटा और देश के कई अन्य हिस्सों में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। हर बार जांच हुई, रिपोर्टें बनीं, सिफारिशें आईं और फिर धीरे-धीरे सब कुछ भुला दिया गया। यदि इस बार भी हम केवल शोक व्यक्त करके आगे बढ़ गए, तो यह उन मासूम बच्चों के प्रति अन्याय होगा जिनके सपने और जीवन इन दुर्घटनाओं की भेंट चढ़ जाते हैं। अंततः यह समझना होगा कि बच्चों की सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है और केवल अभिभावकों का दायित्व भी नहीं। यह एक साझा उत्तरदायित्व है जिसमें संस्थान, सरकार, समाज, मीडिया और परिवार सभी की भूमिका है। जब तक जवाबदेही की संस्कृति विकसित नहीं होगी, तब तक नियम केवल कागजों में रहेंगे और हादसे दोहराए जाते रहेंगे। आज आवश्यकता है कि हर अभिभावक अपने बच्चे के संस्थान की सुरक्षा व्यवस्था की व्यक्तिगत रूप से जांच करे। संचालकों से सवाल पूछे, प्रमाण मांगे और संतोषजनक उत्तर न मिलने पर आवाज उठाए। बच्चों के जीवन से बड़ा कोई समझौता नहीं हो सकता।

लखनऊ का यह अग्निकांड केवल एक शहर की त्रासदी नहीं है। यह पूरे देश के लिए चेतावनी है। यदि हम अब भी नहीं जागे, तो अगली खबर किसी और शहर से आएगी, किसी और परिवार की दुनिया उजड़ जाएगी और हम फिर वही सवाल पूछेंगे—क्या हमारे बच्चों की सुरक्षा सिर्फ खबर बनकर रह जाएगी?

समय आ गया है कि इस सवाल का जवाब शब्दों से नहीं, ठोस कार्रवाई से दिया जाए।

डिप्रेशन से छुटकारा दिला सकता है चीकू

आलू की तरह दिखने वाला फल चीकू सपोटा के नाम से भी जाना जाता है। चीकू में विटामिन-बी, विटामिन ई, पोटेशियम,फाइबर और मिनरल आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जो शरीर को कई बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। चीकू खाने से त्वचा, दिमाग और पाचन अच्छा रहता है। चीकू खाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है। चीकू का हर भाग स्वास्थ्य लाभों से भरा है इसके पत्ते, जड़ और छाल को औषधी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं चीकू खाने से व्यक्ति को मिलते हैं कौन से गजब के फायदे।

हड्डियां बनाए रखे मजबूत

चीकू में कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। चीकू का रोजाना सेवन हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। चीकू खाने से बुढ़ापे की वजह से होने वाली कमजोर हड्डियों को ठीक करने में भी मदद मिलती है।

एनर्जी

चीकू को एनर्जी का अच्छा सोर्स माना जाता है। इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट शरीर को एनर्जी देने का काम करते हैं। जिन लोगों को एनर्जी की कमी महसूस होती है उनके लिए चीकू का सेवन फायदेमंद हो सकता है।

वेट लॉस

चीकू शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को लंबे समय तक भूख का अहसास नहीं होता और वेट लॉस में मिलती है। चीकू को दिन में किसी भी समय खाया जा सकता है। ये शरीर को तुरंत एनर्जी देने के साथ शरीर को मजबूत भी बनाता है।

डिप्रेशन में राहत

चीकू दिमाग को सेहतमंद बनाए रखने के साथ नींद न आने की समस्या को भी दूर करता है। चीकू का सेवन करने से गहरी और अच्छी नींद आती है। चीकू में मौजूद तत्व दिमाग में ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं चीकू का सेवन डिप्रेशन को दूर करने के लिए भी किया जा सकता है।

इन टिप्स से रखें मेंटल हेल्थ का ख्याल

आजकल तनाव न चाहते हुए भी हम सभी की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। स्ट्रेस का बुरा असर, हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर होता है। अक्सर फिजिकल हेल्थ खराब होने पर जब इसके लक्षण नजर आते हैं, तो हम आसानी से इन्हें समझ लेते हैं और इसे ठीक करने की कोशिश में भी लग जाते हैं। लेकिन, मेंटल हेल्थ खराब होने पर इसके लक्षणों को हम या तो समझ नहीं पाते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। खासकर महिलाएं अपनी मेंटल हेल्थ पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती हैं। तनाव और चिंता की वजह से अगर आपके चेहरे की मुस्कुराहट भी कहीं खो गई है, तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है।

मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए फॉलो करें ये टिप्स

- एक्सपर्ट का कहना है कि मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए, डाइट बहुत जरूरी है। डाइट में पोषक तत्वों की कमी भी मेंटल हेल्थ पर असर डाल सकती है।
- अगर आप अधिक तनाव में हैं और इसकी वजह से आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है या आप हर वक्त परेशान रहती हैं, तो किसी से इस बारे में खुलकर बात जरूर करें।
- ओवरथिंकिंग की वजह से भी मेंटल हेल्थ खराब होती है। इसलिए, किसी भी चीज या डर को लेकर, बहुत अधिक न सोचें वरना इसका असर आपकी सेहत पर हो सकता है।
- किसी बात को बार-बार सोचने से, स्ट्रेस और एंग्जायटी बढ़ने लगती है। इसकी वजह से सिरदर्द, शरीर में दर्द और घबराहट हो सकती है। इसलिए, ज्यादा न सोचें और मन को शांत रखने की कोशिश करें।
- एक्सरसाइज, मेडिटेशन और प्राणायाम भी मेंटल हेल्थ सुधारने में मदद कर सकता है। इसलिए, इसे रूटीन का हिस्सा जरूर बनाएं।
- जब आपको स्ट्रेस या एंग्जायटी महसूस हो, तो गहरी सांस लें और कुछ देर के लिए सारी चीजों पर से ध्यान हटाने की कोशिश करें।
- दिन में कुछ समय उन चीजों को जरूर दें, जो आपको खुशी देती हों।

पैरों के तलवे में होती है जलन इन टिप्स से मिलेगा आराम

क्या आपको भी पैरों के तलवे में जलन होती है, जलन के मारे काम करना भी मुश्किल हो जाता है तो हम आपको कुछ आजमाए हुए टिप्स बता रहे हैं जिससे आपको काफी आराम मिल सकता है। अक्सर लोगों को पैरों के तलवे में जलन की शिकायत होती है। यह एक असहज और परेशान करने वाली समस्या होती है, कई बार जलन के कारण नींद भी नहीं आती है और काम भी प्रभावित होता है। अगर आप भी इस स्थिति का सामना करते हैं तो हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिससे आपको तलवे में जलन से राहत मिल सकती है।

पैरों के तलवे में जलन क्यों होती है?

- पैरों की अत्यधिक गर्मी के कारण ऐसा हो सकता है। अगर आप लंबे वक्त तक जूते पहने रह सकते हैं तो इसके कारण तलवे में जलन हो सकती है।
- खराब रक्त प्रवाह के कारण भी पैरों के तलवे में जलन हो सकती है।
- शरीर में आयरन और विटामिन B12 की कमी के कारण भी यह समस्या हो सकती है।

पैरों के तलवे की जलन दूर करने के उपाय

- तलवे में अगर बहुत ज्यादा जलन होती है तो आप ठंडा पानी में 20 मिनट तक पैरों को डूबा कर रख सकते हैं। आप चाहे तो इसमें कुछ बर्फ के टुकड़े डाल सकते हैं, इससे काफी आराम महसूस होगा।
- इसके अलावा आप तलवे में हो रही जलन को दूर करने के लिए तलवों की मालिश कर सकते हैं, मालिश करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और जलन में आराम मिलता है।
- अपने आहार में आयरन विटामिन B12 जैसे पोषक तत्व शामिल करें, इससे शरीर में खून बढ़ता है और रक्त प्रवाह को बनाए रखने में मदद मिलती है।
- तलवे के जलन को कम करने के लिए आप मेहंदी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रात के समय पैरों में मेहंदी लगा लें और सुबह उठकर धो लें इससे तलवे में ठंडक मिलती है।
- इसके अलावा आप पैरों में एलोवेरा और चंदन का लेप लगा सकते हैं। इन दोनों ही चीजों की तासीर ठंडी होती है। इसका पेस्ट बना ले और तलवे पर भी 20 मिनट तक लगा कर रखें, फिर साफ पानी से धो लें।
- अगर इन उपायों को आजमाने के बाद भी आपको राहत नहीं मिलती है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।

देखने की क्षमता प्रभावित करता है प्रेसबायोबिया विकार

प्रेसबायोबिया आंखों से जुड़ी एक बीमारी जिसमें आंखों की करीब वस्तुओं पर फोकस करने की क्षमता कम हो जाती है।

प्रेसबायोपिया आंखों से संबंधित एक विकार है। इस शब्द को ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बूढ़ी आंख, यह एक ऐसी स्थिति होती है जब आपकी धीरे-धीरे चीजों को करीब से स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता खो देती है। इस स्थिति में नजदीकी वस्तुओं पर तेजी से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता धीरे-धीरे खत्म हो जाती है। आमतौर पर यह 40 से 45 साल की उम्र में शुरू होती है और समय के साथ बिगड़ती जाती है। यह बाकी उम्र से संबंधित दृष्टि समस्याओं जैसे अंधापन, हाइपरोपिया मायोपिया से अलग है। यह एक प्राकृतिक परिवर्तन है जो लगभग सभी लोगों को प्रभावित करता है। इसको लेकर हमने हेल्थ एक्सपर्ट से बाती है।

प्रेसबायोपिया के लक्षण

- छोटी लेखन सामग्री पढ़ने में कठिनाई होती है, खासकर अगर रोशनी बहुत कम है।
- जब आपको यह बीमारी होती है तो आप अपने स्मार्टफोन या किसी भी किताब, मेनू , लेबल को अधिक स्पष्ट रूप से देखने के लिए अपनी आंखों से दूर रखते हैं।
- कोई नजदीकी काम करते हैं या कुछ नजदीक रखकर पढ़ते हैं तो इसे सिर में दर्द और आंखों में तनाव होना।

प्रेसबायोपिया के कारण

- आंखों की उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया प्रेसबायोपिया की ओर ले जाती है।
- समय के साथ आंखों का आंतरिक लेंस लचीला नहीं रहता है, जिससे नजदीकी वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है।
- उम्र के साथ लेंस को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियां कमजोर हो जाती है।
- यह अनुवांशिक भी हो सकती है। अगर आपके घर में माता-पिता या दादा- दादी कोप्रेसबायोपिया था तो आपको भी यह स्थिति होने की संभावना ज्यादा रहती है।
- डायबिटीज,उच्च रक्तचाप और दिल की बीमारी सहित कई स्वास्थ्य स्थितियों में भीप्रेसबायोपिया हो सकता है।
- आंखों की चोट के कारण भी लेंस को नियंत्रित करने वाले मांसपेशियों को नुकसान पहुंच सकता है,इससे भी प्रेसबायोपिया हो सकता है।

डाइट से एडेड शुगर हटाना फायदेमंद!

चीनी...यह एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही मुंह में मिठास घुलने लगती है। चीनी जिस तरह से हर मिठाई, हलवे और खीर का स्वाद बढ़ाती है, उसी तरह से बीमारियों का खतरा भी बढ़ाती है। वजन बढ़ने से लेकर डायबिटीज तक, चीनी शरीर के लिए कई तरह से नुकसानदायक मानी जाती है। ऐसे में कई लोगों ने चीनी को अपनी डाइट से पूरी तरह से हटा दिया है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चीनी को अपनी थाली से बिल्कुल नहीं निकाल पा रहे हैं और भरपूर मीठा खा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दिन में कितना चीनी यानी शुगर का सेवन करना आपके लिए सेफ है।

अति किसी भी चीज की बुरी होती है, यह बात चीनी के सेवन के मामले में भी लागू होती है। डॉक्टर्स से लेकर हेल्थ एक्सपर्ट भी इस बात को मानते हैं कि व्हाइट शुगर सेहत के लिए कई तरह से हानिकारक होती है। अब इस बात पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी मुहर लगा दी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशियन ने कुछ समय पहले भारतीयों की डाइट को लेकर 17 गाइडलाइन्स की एक ज्वाइंट रिपोर्ट जारी की थी। जिसमें से एक गाइडलाइन में भारतीयों को एक दिन में कितनी शुगर लेनी चाहिए, इसका जिक्र किया गया है।

एक दिन में कितनी चीनी का सेवन करना चाहिए?

अगर एक सामान्य एड्ल्ट प्रति दिन 2000 कैलोरी लेता है और इसका 5 परसेंट यानी 25 ग्राम शुगर इन्टेक करता है तो वह हाई शुगर कहलाता है। अगर इसे सामान्य भाषा में समझें 20-25 ग्राम शुगर का एक दिन में सेवन किया जा सकता है।

संभव रहे तो चीनी को अपनी डाइट से पूरी तरह से हटा देना चाहिए। क्योंकि इसमें कैलोरी के अलावा किसी भी तरह के न्यूट्रिशियन शामिल नहीं होते हैं। कैलोरी शरीर के लिए तभी फायदेमंद होती है जब विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर के साथ ली जाए।

रिपोर्ट के मुताबिक, एडेड शुगर को अपनी डाइट से पूरी तरह से हटा देना फायदेमंद होता है। एडेड शुगर में चीनी, गुड़, ग्लूकोज, फ्रूक्टोज, डेक्सट्रोज, शुगर सिरप आदि चीजें आती हैं। किसी भी चीज में शुगर को मिलाकर खाना सेहत के लिए किसी भी तरह से बेहतर नहीं होता है क्योंकि इससे शरीर में सिर्फ कैलोरी बढ़ती है। चीनी के बहुत सारे नुकसान होते हैं।

क्या नेचुरल शुगर है सेफ?

रिपोर्ट में फलों और दूध में पाई जाने वाली शुगर को नेचुरल बताया है। फलों और खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से मौजूद रहने वाली शुगर को एक्सपर्ट भी सेफ मानते हैं. लेकिन सभी फलों और खाने की चीजों में मौजूद शुगर आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होती है। मेडिकल बॉडी ने अपनी रिपोर्ट में गन्ने के जूस को सेहत के लिए हानिकारक माना है। गन्ने के जूस में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और यह आपको बीमार कर सकती है। 100 द्रव्य के गन्ने के जूस में 15 ग्राम शुगर होती है, ऐसे में इसका अधिक सेवन आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। शरीर में अत्यधिक शुगर से कई बीमारियों को न्योता मिल सकता है।

रिपोर्ट में सॉफ्ट ड्रिंक्स के सेवन पर भी ऐतराज जताया गया है. मेडिकल बॉडी का मानना है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में सिर्फ हाई शुगर कंटेंट होता और न्यूट्रिशियनल वेल्यू ना के बराबर होती हैं। ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स के सेवन से मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, दांतों की समस्या और दिल की बीमारी भी हो सकती है। साथ ही सॉफ्ट ड्रिंक्स पानी और फ्रेश फ्रूट्स की जगह नहीं ले सकते हैं, ऐसे में उन्हें जितना हो सके इनका सेवन करने से बचना चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स की जगह छाछ, नींबू पानी, बिना चीनी वाले फ्रूट जूस और नारियल पानी के सेवन की सलाह दी गई है। जूस से ज्यादा फलों के सेवन पर भी जोर दिया है। रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि फ्रूट फाइबर और न्यूट्रियंट वेल्यू की वजह से ज्यादा सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं।

गाइडलाइन्स में भारतीयों की हेल्दी डाइट पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट में हरी सब्जियों के अत्याधिक सेवन की बात की गई है और डाइट से प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड जूस, सॉफ्ट ड्रिंक को हटाने की सलाह दी गई है। साथ ही चाय और कॉफी के सेवन को भी कम करने की बात की गई है, क्योंकि इसमें कैफीन होता है जो सेहत के लिए हानिकारक साबित साबित हो सकता है।

कभी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ना चाहती थीं निवेथा पेथुराज, 'सिंग गीतम' बना करियर का टर्निंग पॉइंट

साउथ फिल्म इंडस्ट्री को कई सफल फिल्में देने वाली अभिनेत्री निवेथा पेथुराज ने बताया कि साल 2023 में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना लिया था। हालांकि, बाद में परिस्थितियां बदलीं और उन्हें निर्देशक सिंगीतम श्रीनिवास राव की फिल्म 'सिंग गीतम' का हिस्सा बनने का अवसर मिला, जिसने उनके करियर को नई दिशा दी। फिल्म 'सिंग गीतम' की सफलता के बाद आयोजित थैंक्सगिविंग इवेंट में निवेथा ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब वह अभिनय की दुनिया से दूर जाना चाहती थीं। उनके अनुसार, जीवन कभी-कभी ऐसे रास्तों पर ले जाता है, जहां से उसे अपने लिए सही मंजिल का पता चलता है। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने उस समय सिनेमा छोड़ने का फैसला कायम रखा होता, तो शायद आज वह इस खास फिल्म का हिस्सा नहीं बन पातीं।

निवेथा ने फिल्म के निर्माता नाग अश्विन का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नाग अश्विन ने उन्हें दोबारा आत्मविश्वास दिया और अभिनय की दुनिया में लौटने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान अभिनेत्री भावुक नजर आईं, उन्होंने कहा कि यदि नाग अश्विन का सहयोग नहीं मिला होता, तो वह शायद किसी शांत स्थान पर आध्यात्मिक जीवन जी रही होतीं। उन्होंने स्वीकार किया कि वह एक अलग जीवन चुनने की सोच रही थीं, लेकिन अब वह पूरी ऊर्जा और विश्वास के साथ अपने करियर में वापस लौट चुकी हैं।

अभिनेत्री ने फिल्म देखने के दौरान अपने भावनात्मक अनुभव का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि फिल्म की कहानी और उसका मैसेज उन्हें बेहद प्रभावित कर गया। उनके अनुसार, यह फिल्म वर्तमान समय की कई महत्वपूर्ण सामाजिक और पर्यावरण संबंधित चुनौतियों को पेश करती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि हर शिशु के जन्म पर एक पौधा लगाने की पहल की जाए, जिससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिल सके।

निवेथा ने यह भी कहा कि उन्हें म्यूजिक बेस्ड फिल्मों और म्यूजिक इवेंट्स से खास लगाव है। उन्होंने बताया कि वह अक्सर लंदन में आयोजित म्यूजिक फेस्टिवल्स में शामिल होती रही हैं और भारत में भी ऐसे आयोजनों की उम्मीद करती थीं। ऐसे में 'सिंग गीतम' जैसी म्यूजिकल फिल्म का हिस्सा बनना उनके लिए बेहद खास अनुभव रहा।

कार्यक्रम के दौरान उन्होंने निर्देशक सिंगीथम श्रीनिवास राव की भी जमकर तारीफ की। निवेथा ने उन्हें 'डायरेक्टर्स के डायरेक्टर' बताते हुए कहा कि उनके साथ काम करना उनके करियर के सबसे यादगार अनुभवों में से एक है। उन्होंने फिल्म की पूरी टीम का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन पर भरोसा जताने के लिए वह सभी की आभारी हैं।

पर्सनल ट्रेनर 2 में नया अवतार दिखाएंगी टीना दत्ता

ओटीटी की दुनिया में नई वेब सीरीज 'पर्सनल ट्रेनर 2' को लेकर खूब चर्चा हो रही है। इसमें टीवी की जानी-मानी अभिनेत्री टीना दत्ता फिटनेस ट्रेनर नेहा मल्होत्रा नाम का किरदार निभा रही हैं। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर करते हुए कहा कि वह भूमिका से तुरंत जुड़ गईं, क्योंकि असल जिंदगी में फिटनेस उनके जीवन का अहम हिस्सा है। वह योग, जिम और पिलेट्स रोजाना करती हैं, जिससे उन्हें इस किरदार को समझने में आसानी हुई। अभिनेत्री टीना दत्ता ने कहा, ''मेरा किरदार नेहा मल्होत्रा फिटनेस की शौकीन है। उसके कई शेड्स हैं। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, इस किरदार की असली सच्चाई और उसके अलग-अलग पहलू धीरे-धीरे सामने आते जाएंगे। यही इस भूमिका को दिलचस्प बनाता है।'' टीना दत्ता ने कहा, ''इस सीरीज में दर्शक मुझे एक ऐसे अवतार में देखेंगे, जो पहले मैंने कभी नहीं निभाया था। जैसे ही मुझे इस शो के पहले सीजन की कहानी समझ आई थी, तभी मैंने दूसरे सीजन के लिए तुरंत हामी भर दी थी। यह प्रोजेक्ट मेरे करियर में एक नया और अलग अनुभव जोड़ने वाला है।''

इस सीरीज में टीना के साथ आकांक्षा पुरी, पूनम पांडे और राहुल सुधीर जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। टीना दत्ता ने सीरी में काम करने के अनुभव को लेकर कहा, ''शूटिंग के दौरान मेरा अनुभव काफी अच्छा रहा, खासकर आकांक्षा पुरी के साथ काम करना मेरे लिए बेहद सुखद रहा। हम दोनों ही फिटनेस को लेकर काफी गंभीर हैं, इसलिए सेट पर अक्सर हम एक-दूसरे से वर्कआउट और हेल्थ टिप्स शेयर करते रहते थे। इससे शूटिंग का माहौल और भी सकारात्मक और ऊर्जा से भरा रहता था।''बता दें कि 'पर्सनल ट्रेनर 2' मुंबई के हाई-प्रोफाइल जिम्स की दुनिया पर आधारित है, जहां फिटनेस के अलावा, पावर गेम्स और छुपी हुई राजनीति भी चलती है। यह सीरीज दिखाती है कि कैसे चमकदार लाइफस्टाइल के पीछे कई बार गहरे राज और संघर्ष छिपे होते हैं।

जैकलीन फर्नांडीज अपनी पहली पूर्ण हॉरर फिल्म में आएंगी नजर

जैकलीन फर्नांडीज जल्द ही अपनी पहली पूर्ण हॉरर फिल्म के साथ इस शैली में कदम रखने जा रही हैं। अभिनेत्री काफी समय से इस जॉनर में एक मजबूत और अलग कहानी की तलाश में थीं और अब उन्हें ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया है जिसने उन्हें बेहद उत्साहित कर दिया है।सूत्रों के अनुसार, यह फिल्म हॉरर, इमोशन और म्यूजिक का बेहतरीन मिश्रण होगी, जो दर्शकों को एक संपूर्ण सिनेमाई अनुभव देगी। फिल्म में जैकलीन मुख्य भूमिका निभाएंगी, जबकि दो मेल एक्टर्स को पहले ही फाइनल किया जा चुका है। फिलहाल फिल्म का टाइटल, अन्य कलाकारों के नाम और निर्देशक की जानकारी गुप्त रखी गई है।इस फिल्म का निर्माण ख्याति मदान के बैनर नॉट आउट एंटरटेनमेंट के तहत बड़े स्तर पर किया जाएगा। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है।सूत्रों का यह भी कहना है कि फिल्म का एक टीज़र और एक गाना पहले ही शूट किया जा चुका है, जबकि कलाकार इन दिनों वर्कशॉप्स में हिस्सा ले रहे हैं। फिल्म की शूटिंग इस महीने के अंत तक शुरू होने की संभावना है।दिलचस्प बात यह है कि जैकलीन इससे पहले भूत पुलिस में नजर आ चुकी हैं, लेकिन वह एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म थी। यह नई फिल्म उनके करियर की पहली पूरी तरह हॉरर फिल्म होगी।वर्क फ्रंट की बात करें तो जैकलीन हाल ही में हाउसफुल 5 में नजर आई थीं और अब वह वेलकम टू द जंगल में दिखाई देंगी, जो 26 जून 2026 को रिलीज होने वाली है।

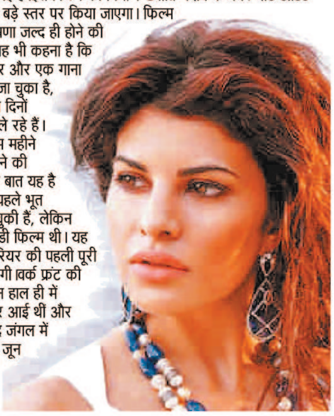

'ढिंढोरा 2' लेकर आएंगे भुवन बाम, नए किरदार की होगी एंट्री

यूट्यबर से एक्टर बने भुवन बाम की वेब सीरीज 'ढिंढोरा 2' जल्द ही दर्शकों को देखने को मिलेगी। इसकी शूटिंग वह इन दिनों कर रहे हैं। इस वेब सीरीज में एक नए किरदार की एंट्री भी होने वाली है। समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' ने भुवन ने अपनी वेब सीरीज की शूटिंग का जिक्र किया। साथ ही समय रैना के शो में आने की बात भी कही।

भुवन बाम ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शो 'ढिंढोरा 2' की घोषणा की। वह सीरीज के किरदार टीटू मामा के गेटअप में नजर आए। उनके साथ एक महिला किरदार भी खड़ी दिखीं। 'ढिंढोरा 2' में वह इस बार नए किरदार की एंट्री करेंगे। समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' के पहले एपिसोड में भी भुवन बाम ने फोन बताया कि वह 'ढिंढोरा 2' की शूटिंग कर रहे हैं। दरअसल, समय रैना ने एक प्रतियोगी की बात फोन पर भुवन बाम से करवाई थी, वह प्रतियोगी भुवन का बहुत बड़ा फैन था।

भुवन ने ही लिखी है 'ढिंढोरा 2'

'ढिंढोरा 2' को भुवन बाम, अब्बास दलाल, हुसैन दलाल, चेतन डांगे, गोपाल दत्त, शुभम दुबे और अनंत दुबे ने लिखा है। इसे रोहित राज और भुवन बाम ने प्रोड्यूस किया है। इस वेब सीरीज के पहले सीजन को फैंस ने खूब पसंद किया था।

मल्टी टैलेंटेड हैं भुवन बाम

भुवन बाम एक चर्चित कॉमेडियन, एक्टर, राइटर, सिंगर और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं। उन्होंने यूट्यूब पर भारत में ऑनलाइन स्केच कॉमेडी की शुरुआत की थी। उन्हें अपने चैनल 'बीबी की वाइन' से पहचान मिली, जहां वे मजेदार और अनोखे किरदारों को खुद ही निभाते हैं।

रणवीर शौरी ने बताया क्यों हर बार नया करने की करते हैं कोशिश

एक्टर रणवीर शौरी अपनी वर्सटैलिटी के लिए जाने जाते हैं। वो अक्सर अपने किरदारों के साथ प्रयोग करते रहते हैं। एक्टर का मानना है कि उन्हें टाइपकास्ट होने से सबसे ज्यादा डर लगता है। इसीलिए वो अपने किरदारों के साथ अलग-अलग तरह का प्रयोग करते रहते हैं।

मैंने एक जैसे रोल दोहराने की कोशिश नहीं की

पीटीआई के साथ हालिया बातचीत में रणवीर शौरी ने अपने किरदारों और टाइपकास्ट होने के डर को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी एक जैसे रोल दोहराने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री के बाहरी दायरे में पला-बढ़ा हूं। जब से मैं एक्टर बना हूं, टाइपकास्टिंग का डर मुझे परेशान करता रहा है और इसी बात ने मेरे कई फैसलों पर असर डाला है। इसलिए हर बार मैं कुछ नया और बिल्कुल अलग करने की कोशिश करता हूं। मेरी यही कोशिश रहती है।

'पिरामिड स्कीम' में नजर आए रणवीर

रणवीर शौरी हाल ही में प्राइम वीडियो की सीरीज 'पिरामिड स्कीम' में नजर आए हैं। सात एपिसोड की यह सीरीज भारत में 'मल्टी-लेवल मार्केटिंग' (रूरूरू) और पोंजी स्कीम के नाम पर होने वाले करोड़ों के घोटालों की कड़वी सच्चाई को उजागर करती है। सीरीज की कहानी सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हरिद्वार पर आधारित है। इसमें गोल्डी नाम के एक आकर्षक और मेहनती युवा की कहानी है जो बेहतर जिंदगी की तलाश में है, लेकिन किसी तरह पिरामिड मार्केटिंग की चकाचौंध भरी और अजीब तरह से भरोसेमंद लगने वाली दुनिया में फंस जाता है। इस सीरीज को श्रेयांश पांडे ने बनाया है और आशीष आर. शुक्ला और पांडे ने इसे डायरेक्ट किया है।

आयुष्मान खुराना से लेकर तापसी पन्नू तक, इन एक्टर्स ने अच्छी-खासी नौकरी छोड़कर फिल्मी दुनिया में रखा कदम

बॉलीवुड के कई ऐसे सितारे हैं, जो फिल्मों से पहले अच्छी-खासी नौकरी करते थे, लेकिन उनका मुकाम वो नहीं था। इसीलिए उन्होंने नौकरी छोड़कर फिल्मों की और रुख किया। जानिए कुछ ऐसे ही सितारों के बारे में, जो पहले कुछ और थे, और अब जानी-मानी हस्ती। फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाना आसान नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे स्टार्स भी हैं, जिन्होंने अपनी अच्छी-खासी नौकरी छोड़कर अपने सपनों के पीछे दौड़ लगाई और आखिरकार बड़ी सफलता हासिल की। जानिए कौन थे वो एक्टर्स, जिन्होंने नौकरी छोड़कर फिल्मी दुनिया में कदम रखा।

आयुष्मान खुराना

फिल्मों में आने से पहले आयुष्मान खुराना रेडियो जॉकी और टीवी प्रेजेंटर थे। उन्होंने एक सुरक्षित मीडिया करियर छोड़कर बॉलीवुड में कदम रखा और सफल हुए।

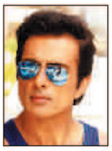

सोनू सूद

एक्टर बनने से पहले सोनू सूद ने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इंजीनियर के तौर पर काम भी किया। लेकिन उन्होंने यह सुरक्षित करियर छोड़कर मुंबई का रुख किया और एक्टिंग में अपना नाम बनाया।

आर. माधवन

स्टार बनने से पहले आर. माधवन पब्लिक स्पीकिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर थे। बाद में उन्होंने अपना करियर बदला और टीवी व फिल्मों में एंट्री की।

परिणीति चोपड़ा

परिणीति चोपड़ा का करियर कॉर्पोरेट दुनिया में था। वह यशराज फिल्म्स के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करती थीं, लेकिन बाद में उन्होंने एक्टिंग में डेब्यू किया।

विक्रांत मैसी

विक्रांत मैसी ने कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। उनके पास दूसरे प्रोफेशनल करियर के मौके भी थे, लेकिन उन्होंने पूरी तरह एक्टिंग पर फोकस किया और आज उन्हें काफी सराहना मिलती है।

हर्षवर्धन राणे

हर्षवर्धन राणे ने 200 रुपये लेकर मुंबई आए थे। फिल्मों से पहले वो हॉटल में वेटर के तौर पर काम करते थे, जिसके बदले में उन्हें 10 रुपये मिलते थे। इसके अलावा उन्होंने एसटीडी बूथ पर भी काम किया है। काफी समय बाद उन्हें मौका मिला और फिर एक फिल्म आई – 'सनम तेरी कसम', जिसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई।

रणविजय सिंह

रणविजय सिंह पहले आर्मी में जाने की तैयारी कर रहे थे और उनके पास कई दूसरे करियर ऑप्शन भी थे। लेकिन MTV रोडीज ने उनकी जिंदगी बदल दी और वह टीवी पर्सनैलिटी बन गए।

तापसी पन्नू

तापसी पन्नू ने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की है और वह सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल के तौर पर काम कर चुकी हैं। बाद में उन्होंने मॉडलिंग और फिर फिल्मों की दुनिया में कदम रखा।

निगम आयुक्त ने ली परामर्शदात्री समिति की बैठक, वेतन-नियुक्ति-पेंशन पर की गई चर्चा

कर्मचारी संघों ने उठाए पदोन्नति, अनुकंपा नियुक्ति और बकाया भुगतान के मुद्दे

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने बुधवार को विभिन्न कमर्चारी संघों के पदाधिकारियों के साथ परामर्शदात्री समिति की बैठक ली। बैठक में कमर्चारी हितों से जुड़े वेतन, अनुकंपा नियुक्ति, पदोन्नति और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया भुगतान जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।

कर्मचारी संघों ने रखी ये प्रमुख मांगें

बैठक में संघ पदाधिकारियों ने हर माह समय पर वेतन भुगतान, कर्मचारियों की पदोन्नति-क्रमोन्नति, मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग प्रमुखता से उठाई। इसके अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवकाश नगदीकरण, भविष्य निधि की कटी हुई राशि, नवीन अंशदायी पेंशन की जमा न होने वाली राशि के भुगतान पर भी चर्चा की गई।

प्लेसमेंट कर्मचारियों को लंबे समय से वेतन न मिलने, ईपीएफ राशि जमा न होने, कर्मचारी क्वार्टरों की मरम्मत और सेवानिवृत्त कमर्चारी संघ को गतिविधियों के संचालन के लिए राशि देने का मुद्दा भी उठाया गया।

आयुक्त ने दिया आश्वासन

आयुक्त विश्वकर्मा ने कहा कि राजस्व वसूली और राशि की उपलब्धता के आधार पर वेतन व सेवानिवृत्त कर्मचारियों का भुगतान किया जाता है। उन्होंने बताया कि एक वर्ष में 23 कमर्चारियों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। 3 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं और पूर्व के 15 आवेदन शासन को भेजे गए हैं। शासन की स्वीकृति के बाद शेष को भी नियुक्ति दी जाएगी।

पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया जा चुका है और नियमानुसार कार्यवाही चल रही है। उन्होंने कहा कि शासन स्तर के प्रकरणों के निराकरण के लिए लगातार पत्राचार किया जा रहा है। सेवानिवृत्त कमर्चारी संघ को बजट प्रावधान के अनुसार राशि देने की प्रक्रिया चल रही है।

आयुक्त ने भरोसा दिलाया कि कमर्चारी संघों की समय-समय पर बैठक बुलाकर स्थानीय स्तर की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा और शासन स्तर के लंबित मामलों के लिए पत्राचार जारी रहेगा।

बैठक में ये रहे उपस्थित

बैठक में कार्यपालन अभियंता दीपक खाण्डे, स्थापना प्रभारी राकेश नंदे मौजूद थे। कर्मचारी संघों से नवयुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ के जिला अध्यक्ष गोकुल प्रसाद कवर, नगर निगम स्वास्थ्य कमर्चारी संघ के अध्यक्ष प्रवीण झा, सफाई कमर्चारी संघ के अध्यक्ष गोलू नायक, प्लेसमेंट ठेका कमर्चारी संघ के अध्यक्ष अजय मेश्राम, सेवानिवृत्त पेंशन संघ के अध्यक्ष दुर्गाराम साहू सहित सभी संघों के पदाधिकारी शामिल हुए।

खास खबर

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में सर्पदंश से बचाव के लिए विशेष स्वास्थ्य जागरूकता अभियान

नई दृष्टिबिंदु / खैरागढ़

सावधानी, सतकर्ता एवं समय पर उपचार से बचाई जा सकती है जान

कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल के निर्देशन में जिला प्रशासन, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के मार्गदर्शन में वर्षा ऋतु के दौरान सपर्दंश की घटनाओं की रोकथाम एवं जनजागरूकता के उद्देश्य से जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा विशेष स्वास्थ्य जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। वर्षा ऋतु में खेतों, झाड़ियों एवं जलभराव वाले क्षेत्रों में साँपों की सक्रियता बढ़ जाती है, जिसके दृष्टिगत आमजन, विशेषकर किसानों, वनांचल क्षेत्रों में निवासरत नागरिकों एवं ग्रामीण परिवारों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आशीष शर्मा ने बताया कि अधिकांश सर्पदंश की घटनाएं खेतों में कार्य करने, झाड़ियों में हाथ डालने अथवा अंधेरे स्थानों में बिना पर्याप्त सावधानी के जाने के कारण होती हैं। वहीं वर्षा ऋतु में साँप सूखी एवं सुरक्षित जगहों की तलाश में घरों, गोठानों तथा आसपास के क्षेत्रों में भी प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए खेतों के साथ-साथ घरों में भी विशेष सावधानी आवश्यक है। स्वास्थ्य विभाग ने सलाह दी है कि खेतों में कार्य करते समय गमबूट अथवा ऊँचे जूते पहनें, झाड़ियों, घास एवं गड्ढों में हाथ डालने से पूर्व डंडे से जांच करें तथा रात्रि के समय टॉर्च का उपयोग अवश्य करें। घर एवं आसपास के क्षेत्रों की नियमित सफाई करें तथा झाड़ियों, लकड़ी, ईंट, पत्थर एवं अनुपयोगी सामग्री के ढेर को हटाकर रखें।

विशेषज्ञों के अनुसार वर्षा ऋतु में खुले स्थानों, खेतों अथवा घर के फर्श पर सीधे सोने से बचना चाहिए। सुबह विश्राम करते समय अथवा रात्रि में सोते समय यथासंभव चारपाई, खाट या ऊंचे बिस्तर का उपयोग करें तथा जमीन पर सोने से बचें। बच्चों को भी फर्श पर न सुलाएं। रात्रि में उठते समय पहले कमरे की रोशनी जलाएं अथवा टॉर्च का उपयोग करें तथा जूते-चप्पल पहनने से पूर्व उन्हें अच्छी तरह जांच लें। स्वास्थ्य विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सर्पदंश की स्थिति में घबराने के बजाय पीड़ित को शांत रखें तथा प्रभावित अंग को यथासंभव स्थिर रखें। प्रभावित स्थान पर चीरा लगाना, जहर चूसने का प्रयास करना, कसकर रस्सी बांधना अथवा झाड़-फूंक एवं अंधविश्वास का सहारा लेना हानिकारक हो सकता है।

सर्पदंश होने पर समय न गंवाएं। पीड़ित को तत्काल निकटतम स्वास्थ्य संस्थान पहुंचाएं। आपातकालीन एम्बुलेंस रेफरल एवं चिकित्सा सहायता हेतु टोल-फ्री नंबर 108 अथवा 112 पर कॉल कर निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा प्राप्त की जा सकती है। समय पर अस्पताल पहुंचना ही सर्पदंश से होने वाली गंभीर जटिलताओं एवं मृत्यु की संभावना को कम करने का सबसे प्रभावी उपाय है। जिले के शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में सपर्दंश पीड़ितों के उपचार हेतु प्रशिक्षित चिकित्सा दल एवं आवश्यक मात्रा में एंटी स्नेक वेनम (एएसवी) उपलब्ध है। समय पर चिकित्सा उपचार प्राप्त होने से अधिकांश मरीजों का सफल उपचार संभव है।

जिला प्रशासन ने सभी जनप्रतिनिधियों, समस्त विभागीय अधिकारियों, कमर्चारियों, सामाजिक संगठनों एवं मितानिनों, नागरिकों से आग्रह किया है कि वर्षा ऋतु के दौरान सर्पदंश से बचाव संबंधी सावधानियों का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। सामूहिक जागरूकता, सतकर्ता एवं समय पर चिकित्सा उपचार से सपर्दंश जनित मृत्यु एवं गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं को प्रभावी रूप से रोका जा सकता है। "सतकर्ता, समय पर उपचार और सही जानकारी ही सर्पदंश से बचाव की सबसे बड़ी कुंजी है।"

पीएमएफएमई योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को मिलेगा 35 प्रतिशत तक अनुदान

खैरागढ़। जिले में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना एवं उन्नयन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। योजना के माध्यम से स्थानीय उद्यमियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने तथा सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को औपचारिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। योजना के तहत आटा चक्की, मसाला पिसाई, टोस्ट निर्माण, बड़ी निर्माण, कुल्फी, आइसक्रीम, मिठाई, चिक्की सहित विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के साथ-साथ पशु चारा एवं मुर्गी चारा निर्माण इकाइयों की स्थापना अथवा उन्नयन के लिए परियोजना लागत पर 35 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किए जाने का प्रावधान है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक आवेदक पीएमएफएमई पोर्टल https://pmfme.mofpi.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ नवीनतम फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की पिछले छह माह की प्रविष्टियों की प्रति, कोटेशन तथा राशन कार्ड की प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।

पीएम आवास सूची विवाद, ग्राम सभा में महिला-बेटी ने आत्मदाह का किया प्रयास

एक महिला ने सूची में अपना नाम शामिल नहीं होने पर कड़ी आपत्ति जताई

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

जिले के सुकुलदैहान पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत ढीलापहरी में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही चयन को लेकर गंभीर विवाद सामने आया है। ग्राम सभा के दौरान आवास सूची में नाम नहीं होने से नाराज एक महिला और उसकी बेटी ने पंचायत भवन के भीतर खुद पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों और पुलिस की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत हितग्राहियों की सूची पर चर्चा की जा रही थी। इसी दौरान एक महिला ने सूची में अपना नाम शामिल नहीं होने पर कड़ी आपत्ति जताई। महिला और उसकी बेटी का आरोप है कि वे लंबे समय से आवास के लिए आवेदन कर रही हैं और उनके पास जनपद पंचायत की पावती भी मौजूद है। उनका कहना है कि जनपद स्तर से तैयार सूची में उनका नाम शामिल था, लेकिन पंचायत स्तर पर उसे हटा दिया गया।

ग्राम सभा के दौरान इस मुद्दे को लेकर सरपंच, सचिव और संबंधित परिवार के बीच तीखी बहस हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद बढ़ने के बाद महिला और उसकी बेटी ने पंचायत भवन के भीतर ही खुद पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़क लिया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही सुकुलदैहान चौकी से एएसआई चंपेश ठाकुर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने दोनों महिलाओं को सुरक्षित जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति सामान्य बताई गई।

इसके बाद पुलिस ने दोनों के बयान दर्ज किए। मामले पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर ने बताया कि महिलाओं का आरोप है कि स्वीकृत सूची में नाम होने के बावजूद उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया। वहीं प्रारंभिक जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि संबंधित महिला के गांव में दो मकान होने की जानकारी मिली है।

प्रशासन अब पूरे मामले की गहन जांच कर रहा है कि हितग्राही चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि, लापरवाही या अनियमितता हुई है या नहीं। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि सूची में नाम हटाए जाने के पीछे वास्तविक कारण क्या थे। पुलिस और प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। यदि किसी स्तर पर गड़बड़ी या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, हालांकि पुलिस की मौजूदगी में स्थिति नियंत्रण में है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

बागनदी पुलिस की बड़ी कार्रवाई : 11.50 लाख का अवैध कबाड़ व ट्रक जब्त

नागपुर ले जाया जा रहा था माल, जबलपुर का चालक गिरफ्तार

नई दृष्टिबिंदु / बागनदी

थाना बागनदी पुलिस ने अवैध कबाड़ कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 लाख 50 हजार रुपये की कबाड़ सामग्री और ट्रक जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के मार्गदर्शन में चल रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई।

मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया ट्रक

थाना प्रभारी नंदकिशोर गौतम ने बताया कि मंगलवार को सूचना मिली कि लीलैंड 16 चक्का ट्रक क्रमांक उ्रॠ 04 खऊ6297 में बड़ी मात्रा में कबाड़ ले जाया जा रहा है। पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर वाहन को रोका। जांच में ट्रक में साइकिल कटिंग, लोहे की चादरें, विभिन्न आकार के सरिया, नट-बोल्ट और अन्य कबाड़ सामग्री मिली।

दस्तावेज नहीं दिखा पाया चालक

पूछताछ में वाहन चालक अतुल मिश्रा, पिता ललन प्रसाद मिश्रा, 55 वर्ष, निवासी दमोह नाका, इमली पेड़ के पास, जबलपुर, मध्यप्रदेश ने बताया कि वह राजनांदगांव से कबाड़ भरकर नागपुर महाराष्ट्र ले जा रहा था। सामग्री के संबंध में वैध दस्तावेज नहीं दिखाने पर पुलिस ने ट्रक सहित पूरा माल जब्त कर लिया। जब्त संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत 11,50,000 रुपये आंकी गई है।

इनकी रही मुख्य भूमिका

पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर तथा एसडीओपी डोंगरगढ़ केशरीनंदन नायक के मार्गदर्शन में हुई कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक नंदकिशोर गौतम, उप निरीक्षक देवादास भारती, आरक्षक टाकेश्वर पटेल और आरक्षक संतोष महिपाल का सराहनीय योगदान रहा। आरोपी चालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

डोंगरगांव की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी, बना नगर पालिका, जताया उपमुख्यमंत्री का आभार

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

राज्य शासन ने डोंगरगांववासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी करते हुए डोंगरगांव नगर पंचायत का नगर पालिका के रूप में उन्नयन कर दिया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। डोंगरगांव नगर पंचायत की सीमाएं ही डोंगरगांव नगर पालिका की सीमाएं होंगी। राज्य शासन के इस निर्णय से पूरे शहर में खुशी एवं उत्साह का वातावरण है।

डोंगरगांव नगर पंचायत के नगर पालिका में उन्नयन के बाद वहां के जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने आज उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव से मुलाकात कर आभार व्यक्त किया। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इससे डोंगरगांव के सुनियोजित विकास को नई दिशा मिलेगी तथा शहरी सुविधाओं के विस्तार के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने डोंगरगांव के जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों को बधाई देते हुए कहा कि नगर पालिका बनने के बाद डोंगरगांव में सड़क, नाली, पेयजल, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट, उद्यान, सामुदायिक भवन सहित विभिन्न आधारभूत सुविधाओं के विकास को गति मिलेगी। साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ भी अधिक प्रभावी ढंग से नगरवासियों तक पहुंच सकेगा। इस दौरान डोंगरगांव नगर पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती अंजू त्रिपाठी, पार्षद मनबोधी पटेल, श्रीमती पदमनी ठाकुर, श्रीमती गायत्री यादव, श्रीमती लीला मंडलोई, डीकेश साहू, दीना पटेल और रामकुमार गुप्ता भी मौजूद थे।

बेमेतरा में हुई कम बारिश, बुवाई बुरी तरह प्रभावित

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

बेमेतरा जिला में इस वर्ष 23 परसेंट ही बारिश हुई है अभी तक, किसानों का बुवाई का समय आ चुका है बेमेतरा में पानी की हो रही दिक्कत और परेशानियों को लेकर बेमेतरा कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई में वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर पानी की एक-एक बूंद के संरक्षण की बात कही।

उन्होंने कहा कि जल का संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है , क्योंकि इस वर्ष बहुत ही कम मात्रा में पानी गिरा है इस वजह से कृषि विभाग और '५' के वैज्ञानिकों ने समितियां तक जानकारी पहुंचाने प्रचार प्रसार कर के किसानों को ऐसी फसल लेने प्रेरित किया है कि दलहन और तिलहन की फसलें ले जिसमें पानी का उपयोग कम हो और फसल पर्याप्त हो, इस वर्ष एनीकट की मॉनिटरिंग करने के लिए भी निर्देशित किया गया है वाटर हार्वेस्टिंग के लिए लोगों को अपने घर में एक सोखता गड्ढा बनाकर जल को रोकने के उपाय करने के लिए कहा गया है।यदि अधिक वर्षा हुई तो बाढ़ आपदा प्रबंधन की टीम को भी तैयार किया जा रहा है।

अवैध खनन पर होगी कार्रवाई, टास्क फोर्स कर रही निगरानी

अवैध खनन को लेकर जिला बेमेतरा सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने कुछ इस प्रकार से भी जानकारी उन्होंने कहा कि जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक कलेक्टर मैडम और एसपी द्वारा ली गई थी, जिसमें की स्पष्ट निर्देश रिवेन्यू , माइनिंग और पुलिस विभाग को दिए गए हैं , रात में पेट्रोलिंग के लिए विशेष बल भी तैनात किया गया है, साथ ही रूटिंग चेकिंग के लिए सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है, ताकि जिले में हो रहे अवैध उत्खनन पर लगाम लगाई जा सके, खनन से संबंधित सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।

मेडिकल कॉलेज की तैयारियां अंतिम चरण में, कलेक्टर गोपाल वर्मा ने किया निरीक्षण

बलौदाबाजार। जिले में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के निर्धारित मानकों के अनुरूप सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर गोपाल वर्मा ने बुधवार को मेडिकल कॉलेज परिसर का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को समयबद्ध ढंग से सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। मेडिकल कॉलेज का संचालन प्रारंभिक चरण में आयुष चिकित्सालय भवन से किया जाएगा। यहां विद्यार्थियों की पढ़ाई, प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक गतिविधियों के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं विकसित की गई हैं। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने लेक्चर हॉल, विभागाध्यक्ष कक्ष, फैकल्टी रूम, डेमोंस्ट्रेशन रूम, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय तथा प्रशासनिक कक्षों का अवलोकन किया। कलेक्टर ने विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए फर्नीचर, विद्युत व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छता एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने परिसर की नियमित साफ-सफाई और रखरखाव पर विशेष ध्यान देने को कहा। इस दौरान कलेक्टर ने जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया और मेडिकल कॉलेज के संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने आईसीयू, विभिन्न वार्डों, चिकित्सकीय उपकरणों तथा मेडिकल शिक्षा से जुड़ी अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का अवलोकन कर अधिकारियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप सभी तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने मेडिकल कॉलेज से संबद्ध डॉक्टर रेजिडेंस हॉस्टल का भी निरीक्षण किया।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर जिला-दुर्ग (छ.ग.)

-:: ईश्तहार ::-

(रा.प्र.क्रं. 20.2006101000173/-ब-121
वर्ष 2025-26

एदत् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक ज्योति देशमुख आ./ध.प. हरिश देशमुख निवासी-जवाहर नगर भिलाई तह. व जिला दुर्ग, द्वारा अपने पुत्र/पुत्री/स्वयं रामधिरज तिवारी उर्फ राजेश तिवारी का जन्म/मृत्यु दिनांक 22/12/20 को बाबादीप सिंह नगर भिलाई तह. व जिला दुर्ग में जन्म/मृत्यु हो जाने के कारण जन्म / मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

अतः जिस किसी व्यक्ति एवं संस्था को इस संबंध में आपत्ति एवं दावा उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 07/07/2026 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 19/06/2026 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पदमुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया हैं।

अतिरिक्त तहसीलदार
उप तहसील भिलाई नगर (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार अहिवारा जिला-दुर्ग (छ.ग.)

रा.प्र.क्रं. / 202606104000067/
अ-6/वर्ष 2025-26
ग्राम बानबरद, प.ह.नं.-06

// उद्घोषणा //

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदिका श्रीबन्ती मन्ना पति सुनील कुमार मन्ना जाति बंगाली निवासी नंदिनी नगर अहिवारा तहसील अहिवारा जिला दुर्ग (छ.ग.) के द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि ग्राम बानबरद, प.ह.नं. 06 तहसील अहिवारा जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 232/1 रकबा 0.07 को भूमिस्वामी / विक्रेता राधिका देवी पति कपिलदेव सिंह निवासी रूवाबांधा तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 05.01.2001 के माध्यम से क्रय किया गया है। किन्तु अपरिहार्य कारणों से नामांतरण नहीं करवा पाये थे। उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर क्रय की गई भूमि पर क्रेता के नाम पर नामांतरण दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया है। जो इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतएव इस आवेदन के संबंध में विधिक आपत्तियों / दावा रखने वाला जिस व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति, दावा हो तो स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से इस न्यायालय में पेशी दिनांक 15/07/2026 को या उसके पूर्व कार्यालयीन दिवस को लिखित में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार आज दिनांक 23/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के सील-मुहर से जारी किया गया है।

पेशी दिनांकः 15/07/2026
जारी दिनांकः 23/06/2025

मुहर

तहसीलदार
अहिवारा, जिला दुर्ग (छ.ग.)

आप एडल्ट कंटेंट का मतलब समझते हैं?

मुद्दे की बात

डॉ.सोनाली चक्रवर्ती के साथ

कुछ सालों पहले की बात है लाइब्रेरी में पत्रिकाएं पलटते हुए मेरी नजर 'मनोहर कहानियां' नामक पत्रिका पर पड़ी और मेरे कदम ठिठक गए। बचपन में 'अपना पुस्तकालय' में जब हम पत्र पत्रिकाएं लेते थे तो मम्मी ने कड़े शब्दों में कह दिया था- "इन पत्रिकाओं को बिल्कुल हाथ मत लगाना"। हर बार ढेर सारी किताबें लेते हुए आसपास 'मनोहर कहानियां' 'सच्ची कहानियाँ' तरह-तरह की किताबें थीं लेकिन हमें मम्मी की आंखें याद आती थी और हम कभी नहीं लेते थे।

आश्चर्य यह कि आज उम्र के इस पायदान पर पहुंच कर भी उन पत्रिकाओं को छूने से पहले हाथ रुक गए और उन्हें देखने की कोई इच्छा ही नहीं जागी। और मुझे स्वनियंत्रण यानी सेल्फ रेगुलेशन का मतलब समझ में आया जिससे आज के बच्चे वंचित है। अचानक मैं सोचने लगी कि ओटीटी पर सेंसर नहीं है क्योंकि उसमें सेल्फ रेगुलेशन का नियम है। साथ ही यह बोध भी हुआ कि अब यह एडल्ट कंटेंट हमारे हाथ के मोबाइल में मौजूद है और अब किसी मम्मी की आंखें यह देखने से बच्चों को रोक नहीं सकती।

गूगल से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में ओटीटी क्रांति की शुरुआत 2008 में रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा BIGFlix लॉन्च करने के साथ हुई। इसके बाद 2013 में Sony Liv और Ditto TV (Zee) आए। हालांकि, 2016 में Netflix और Amazon Prime Video के आगमन और 4G डेटा क्रांति के बाद ही देश में इसका अभूतपूर्व विस्तार हुआ।

हिंदी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हिंसा और अश्लीलता की शुरुआत मुख्य रूप से 2018 के आसपास हुई जब नेटफ्लिक्स पर 'सेक्रेड गेम्स' और ऑल्ट बालाजी पर 'गंदी बात' जैसी वेब सीरीज रिलीज हुई।

पारंपरिक फिल्मों और टीवी सीरियल्स को 'केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड' (CBFC) से गुजरना पड़ता है। इसके विपरीत, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को 'सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियम, 2021' के तहत स्व-विनियमन (Self-Regulation) की स्वतंत्रता मिली, जिससे मेकर्स को बिना सेंसर के बोल्ड और खूंखार कहानियां बनाने की छूट मिल गई।

और कोई आश्चर्य नहीं कि इन दृश्यों ने लोगों के मन से हत्या, रक्त, शव, अवैध संबंध, नशा, अश्लीलता आदि का भय और लज्जा बिल्कुल ही हटा दिया। अब यह सब रोज देखने लायक और आम जीवन का हिस्सा होने लगे और कोई आश्चर्य नहीं कि समाज में अवैध संबंधों और हत्याओं का सिलसिला बढ़ गया। लोगों का अपने मन पर से ही नियंत्रण हट गया तो वह यह फैसला कैसे कर सकते हैं कि उन्हें कौन सा चैनल देखना है? 2001 से 2017 के बीच प्रेम संबंधों के कारण होने वाली हत्याओं में 28% की वृद्धि हुई है।

भारत में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, हर दिन लगभग 470 से 480 लोग आत्महत्या करते है यानी, हर रोज औसतन देश में हर 3 मिनट में एक व्यक्ति अपनी जान ले रहा। स्वनियंत्रण यहां भी बुरी कदर विफल है।

हम बच्चों को यह सीखाने में असफल रहे कि एडल्ट होने का मतलब केवल एडल्ट कंटेंट देखना नहीं है और एडल्ट कंटेंट का मतलब केवल अश्लीलता और नशा नहीं है बल्कि व्यस्क होने पर बहुत सारे अधिकार और कर्तव्य एक साथ मिलते है।

18 वर्ष की आयु पूरी करने पर भारतीय संविधान आपको एक वयस्क और जिम्मेदार नागरिक का दर्जा देता है। इस उम्र में आपके भीतर देश, समाज और अपने अधिकारों के प्रति एक गहरी जिम्मेदारी (कर्तव्य बोध) आनी चाहिए। आपको 18 वर्ष की आयु में मताधिकार का अधिकार मिलता है। देश और समाज के विकास के लिए एक अच्छी सरकार चुनना आपका सबसे पहला कर्तव्य है।

कानून का सम्मान सीखना होता है

भारत के संविधान और देश के कानूनों का पालन करना हर नागरिक का परम कर्तव्य है। यातायात नियमों का पालन करें, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुँचाएं और हमेशा एक अनुशासित नागरिक बनें।

सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। समाज के प्रति जागरूक रहें। अपने आस-पास साफ-सफाई बनाए रखने में सहयोग करें, पर्यावरण का संरक्षण करें और किसी भी प्रकार के भेदभाव (जाति, धर्म, या लिंग) से दूर रहें। करों (Taxes) का भुगतान शुरू कर सकते हैं। जब आप कमाने लगें तो अपनी आय पर ईमानदारी से टैक्स का भुगतान करें। यह देश की अर्थव्यवस्था और विकास की रीढ़ है।

आज की तारीख में हम सब नकारात्मक खबरों को शेयर करते हैं अच्छी खबरों को पीछे छोड़कर सिर्फ यह दिखाने के लिए कि हम इस चीज के कितने विरोध में है! और ऐसा करते हुए हम गलत चीजें, अश्लील बातें करने वाले,,गंदे काम करने वाले लोगों को प्रसिद्ध बनाते हैं जो आगे चलकर उनकी कमाई का साधन बनता है और बच्चों को लगता है कि ऐसा ही कुछ करने से हम प्रसिद्ध हो सकते हैं।

फिर वह अच्छा हो या बुरा हो। सब हमारा नाम तो जानेंगे। माता-पिता, अभिभावक, शिक्षकों एवं वयस्कों की जिम्मेदारी अब पहले से कहीं अधिक है। इस विषय में गंभीर चिंतन करना होगा।

सड़क दुर्घटना में दो पत्रकार हुए घायल

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

सनसिटी क्षेत्र में बीती रात तेज रफ्तार कार और बाइक के बीच हुई टक्कर में दो पत्रकार घायल हो गए। एक के पैर में गंभीर चोट आई है। घटना के बाद उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल लाया गया। आरोप है कि मौके पर कार चालक ने पत्रकारों को कथित तौर पर कुचलने की कोशिश की। इस घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है। जानकरी के अनुसार, एक कार्यक्रम की कवरेज के बाद पत्रकार योगेश साहू और सौरभ अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान सनसिटी के पास एक तेज रफ्तार सफेद रंग की ब्रेजा कार (क्रमांक CG 04 NE 1199) ने अचानक सामने आ गई, जिससे बाइक सवार जा टकराए। हादसे में पत्रकार सौरभ के पैर में गंभीर चोट आई है। पत्रकारों का आरोप है कि जब उन्होंने चालक को मोबाइल कैमरे में कैद करने की कोशिश की तब कार से कई बार कुचलने का प्रयास किया गया।

जिला स्तरीय अंडर 13 एवं अंडर 19 शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन 4 जुलाई से

दुर्ग। छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ के निर्देशन में जिला शतरंज संघ दुर्ग द्वारा स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित स्मृति नगर भिलाई के सहयोग से 4 एवं 5 जुलाई को दो दिवसीय जिला स्तरीय अंडर 13 एवं अंडर 19 शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन स्वामी विवेकानंद भवन स्मृति नगर भिलाई में आयोजित किया गया है। जिला शतरंज संघ दुर्ग के अध्यक्ष ईश्वर सिंह राजपूत सचिव तुलसी सोनी ने स्पर्धा संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि अंडर 13 के दो बालक एवं दो बालिकाओं तथा अंडर 19 में 4 बालक एवं 4 बालिकाओं का चयन राज्य शतरंज चैंपियनशिप के लिए किया जाएगा। ये चयनित खिलाड़ी आगामी राज्य शतरंज चैंपियनशिप में दुर्ग जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। अंडर 13 में प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफी एवं चौथे पांचवें एवं छठवें स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को मोमेंटो प्रदान किया जायेगा। अंडर 19 में प्रथम द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफी एवं पांचवें एवं छठवें स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को मोमेंटो के अलावा दोनों वर्गों में भाग लेने वाले समस्त खिलाड़ियों को मेडल एवं ई सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। तथा राज्य चैम्पियनशिप में चयनित खिलाड़ियों का प्रवेश शुल्क संघ द्वारा वहन किया जाएगा। स्पर्धा में प्रवेश शुल्क पांच सौ रुपए एवं प्रवेश की अंतिम तिथि 2 जुलाई तक निर्धारित है। स्पर्धा के मुख्य निर्णायक इंटरनेशनल आर्बिटर रॉकी देवांगन एवं सहायक के रूप में फीडे आर्बिटर अनिल शर्मा होंगे।

"यह समाचार पत्र आलोक तिवारी द्वारा 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)-490023 से आलोक तिवारी की ओर से प्रकाशित की जाती है, जिसका संपादन आलोक तिवारी द्वारा किया जाता है तथा इसका मुद्रण समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 पर किया जाता है। (समाचार चयन के लिए PRP Act, 2023 के तहत संपादक जिम्मेदार है)। समस्त विवादों का निपटारा न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।" संपादक आलोक तिवारी, मो. 74154-69100